दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

आज का विचार

कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ कर्मों की शीतल धाया में रहो। सपनों की उड़ान वही भरते हैं, जिनके पंख हौसलों से बने होते हैं।

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़। शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 वर्ष 24, अंक 43, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का किया उद्घाटन

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीरवार को भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव-हित पर आधारित होना चाहिए। एआई कुछ देशों या कंपनियों का साधन नहीं बने, बल्कि यह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का माध्यम बने। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए मानव विजन पेश करते हुए कहा कि अवसरों के साथ जोखिम भी हैं, इसलिए इसे मानव-केंद्रित और जिम्मेदार तरीके से विकसित करना जरूरी है।

इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रमुख और उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान 'नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं'की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य एआई को समावेशी, बहुभाषी और वैश्विक विकास का साधन बनाना है।

प्रधानमंत्री ने डीप फेक जैसी चुनौतियों का जिक्र किया और कहा कि जैसे खाने की चीजों पर लेबल लगता है कि उसमें क्या है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी लेबलिंग जरूरी है ताकि लोग सच-झूठ पहचान सकें। इसकी स्पीड और स्केल इतनी बड़ी है कि इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी होगी। एआई को खुली छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कमान हमारे हाथ में होनी चाहिए । विकासशील देशों के लिए एआई को लोकतांत्रिक बनाना जरूरी है। मनुष्यों को सिर्फ डेटा का स्रोत नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि एआई को सशक्तिकरण का माध्यम बनाना होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ एआई से डरते हैं, कुछ इसमें भाग्य देखते हैं। भारत गर्व से कहता है कि हमें एआई में भय नहीं, भाग्य और भविष्य दिखता है। भारत सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग तक मजबूत इकोसिस्टम बना रहा है। सुरक्षित डेटा सेंटर, मजबूत आईटी ढांचा और डायनामिक स्टार्टअप कल्चर भारत को किफायती, स्केलेबल और सुरक्षित एआई का हब बना सकता है। भारत की विविधता, युवा आबादी और लोकतंत्र इसे खास बनाते हैं।

एआई में पादर्शिता जरूरी, बने सबके हित और सबके सुख का साधन : पीएम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को एआई शिखर सम्मेलन में विश्व के समक्ष भारत का सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का बेंचमार्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एआई को कुछ देश और कंपनियां रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच रही हैं। भारत का मानना है कि एआई के लिए पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे विश्व का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट समिट बताया और कहा कि हमें आज यह संकल्प करना चाहिए कि एआई को वैश्विक भलाई (ग्लोबल कॉम गुड) के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एआई से जुड़ा 'मानव'विजन प्रस्तुत किया। मानव विजन का अर्थ है एम (मोरल एंड एथिकल सिस्टम), ए (अकाउंटेबल गवर्नेंस) एन (नेशनल सॉवरेन्टी) ए (एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव) वी (वैलिड एंड लेजिटीमेट)। इस कार्यक्रम में फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रीगण, बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि और प्रौद्योगिकी एवं एआई उद्योग के नेता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि नैतिक और नीतिपरक प्रणालियां यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिक दिशा-निदेर्शों पर आधारित होनी चाहिए। जवाबदेह शासन का अर्थ है कि इसके लिए पारदर्शी नियम और इसकी सशक्त निगरानी होनी चाहिए। राष्ट्रीय संप्रभुता से मतलब है कि डेटा उसके सही स्वामी (संबंधित देश) का है।

डेटा स्वायत्त, नियम पारदर्शी और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो एआई : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एआई एम्पैक्ट शिखरवार्ता में गुरुवार को वैश्विक नेताओं के समक्ष एआई के नैतिक उपयोग को लेकर तीन सुझाव दिए। इसमें डेटा स्वायत्तता, पारदर्शी नियम और मानवीय मूल्य शामिल रहे। विश्व नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के दौरान पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में विश्वास जताया कि यह सम्मेलन वैश्विक एआई इकोसिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इस 'डिसरप्शन'को मानवता के सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना है। नैतिक उपयोग के समुझों पर उन्होंने कहा कि डाटा के मालिकाना हक को सम्मान मिलना चाहिए। एआई ट्रेनिंग के लिए एक डाटा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। डाटा सुरक्षित संतुलित विश्वसनीय होना चाहिए। इसलिए ग्लोबल ट्रस्टेड डाटा फ्रेमवर्क जरूरी है। उन्होंने कहा कि एआई प्लेटफार्म अपने सेफ्टी रूल्स बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखें। हमें ब्लैक बॉक्स के बदले ग्लास बॉक्स अप्रोच चाहिए। जहां सेफ्टी रूल्स देखें और वेरीफाई किए जा सके तब अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होगी और बिजनेस में एथिकल बिहेवियर को भी बूस्ट मिलेगा। एआई रिसर्च में पेपर क्लिप प्रॉब्लम का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई को क्लियर 'मन वैल्यूस और गाइडेंस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी पावरफुल है लेकिन डायरेक्शन हमेशा मानव ही तय करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई में नैतिक व्यवहार का दायरा बहुत बड़ा है।

हम पिछली सरकारों की ओर से की गई लूट खसोट की लीकेज को बंद कर रहे : मान

कहा, किला रायपुर में 8 एकड़ में फैले तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा

- खेलों के बजट में वृद्धि की जाएगीः मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- हर गांव में स्टेडियम बनाए जाएंगेः मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता
लुधियाना

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ऐतिहासिक किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक्स में शामिल होकर खेलों को नशों के खात्मे के लिए सबसे घातक हथियार घोषित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले पंजाब के बजट में खेलों के बजट में वृद्धि की जाएगी, जिससे पंजाब के युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में ले जाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान बंद की गई बैल गाड़ियों की दौड़ों को अब कानून में संशोधन के बाद फिर से शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बच्चे मैदान में पसीना बहाएंगे और घरों को पदक लाएंगे तो किसी भी नशा विरोधी मुहिम की जरूरत नहीं रहेगी।

किला रायपुर खेलों के पुनरुत्थान को पंजाब की ग्रामीण संस्कृति और विरासत की झलक बताते हुए, मुख्यमंत्री ने नई खेल नीति 2023 को राज्य की खेलों की शान को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसके तहत हर गांव में स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि किला रायपुर में आठ एकड़ में फैले तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और गांव में एक आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पिछली सरकारों द्वारा की गई लूट-खसोट की लीकेज को बंद कर रहे हैं, जिससे जनता का पैसा बचाया जा रहा है और इसे सीधे लोगों पर खर्च किया जा रहा है। किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक्स के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, खेल नशों के खात्मे का सबसे घातक हथियार हैं और राज्य सरकार राज्य के आने वाले बजट में खेलों के बजट में वृद्धि करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही खेलों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने आगे कहा, पिछली सरकारों द्वारा युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया था, हमारी सरकार ने इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की अथाह ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। संरचनात्मक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, नई खेल नीति 2023 पंजाब की खेलों की शान को बहाल करने के लिए शुरू की गई थी और अब खेल बजट को भी और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने खेड्डां वतन पंजाब दियां के तीन सीजन सफलतापूर्वक करवाए गए जिसमें एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां हिस्सा लेती दिखीं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पंजाब आज खेलों में देश का नेतृत्व कर रहा है और मुख्य भारतीय टीमों के कप्तान पंजाब से हैं। पंजाब सरकार की नशों के खिलाफ जंग के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार ने राज्य में 'युद्ध नशों के खिलाफ'मुहिम शुरू की है और खेल इस जंग में सबसे बड़ा हथियार हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के हर गांव में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर पंजाब और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। किला रायपुर खेलों को ग्रामीण संस्कृति और विरासत की झलक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, यह खुशी की बात है कि पंजाब सरकार ने इस विरासत को फिर से जीवित किया है। इसे एक ऐतिहासिक पल बताते हुए उन्होंने कहा कि ये खेल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं और लंबे समय से बैल गाड़ियों की दौड़ों को फिर से शुरू करने की मांग की जा रही थी।

उन्होंने कहा, हम ऐतिहासिक पलों के गवाह बन रहे हैं। लोगों को अपने बैलों से बहुत प्यार है और वे उन्हें अपने पुत्रों की तरह पालते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लगातार तीसरे साल किला रायपुर के ग्रेवाल स्टेडियम में ग्रामीण ओलंपिक 2026 करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मेले का मुख्य आकर्षण बैल गाड़ियों की दौड़ें 12 साल के अंतराल के बाद फिर से जीवंत हुई हैं।

राजनीतिक हताशा में आरोपों की राजनीति कर रहा विपक्षः सैनी

- 'ऑपरेशन लोट्स' जैसे आरोप पूरी तरह निराधार, जनता स्वयं बदलाव चाहती है

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब कोई राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता खोने लगता है तो वह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आरोपों की राजनीति करता है। पंजाब में भाजपा की बढ़ती सक्रियता और जनसमर्थन को देखते हुए लगाए जा रहे तथाकथित ह्लऑपरेशन लोट्सह्व जैसे आरोप पूरी तरह निराधार हैं और राजनीतिक हताशा का प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि जनता स्वयं तुलना कर रही है और विकल्प तलाश रही है तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं डाला जाना चाहिए। पंजाब की जनता अब शांति और विकास चाहती है और यह केवल भाजपा ही दे सकती है। जैसे हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है, वैसे ही पंजाब भी बदलाव के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने एमएसपी खरीद के मुद्दे पर विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि आंकड़ों के साथ चर्चा हो तो ह्लदूध का दूध और पानी का पानीह्व हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि किसान धरनों पर बैठा रहे, जबकि हमारी सरकार चाहती है कि किसान खेती कर देश और प्रदेश को खुशहाल बनाए । 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, यह कोई जुमला नहीं बल्कि हकीकत है।

अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ व्यापार से किसानों और उद्योग को लाभ

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से देश के किसानों को लाभ होगा। हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य के किसान बासमती चावल, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच बना सकेंगे। साथ ही यूरोपीय संघ के साथ टैक्टाइल, ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

बुजुर्ग पेंशन पर विपक्ष फैला रहा भ्रम

बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष संवेदनशील विषय पर झूठ और भ्रम फैलाकर सस्ती लोकप्रियता लेना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन दो लाख मामलों का उल्लेख किया जा रहा है, उनमें से 1 लाख तीन हजार से अधिक मामलों में लाभार्थियों का निधन हो चुका था। लगभग 37 हजार मामलों में आयु गलत दर्ज करवाई गई थी और 39 हजार मामलों में सत्यापन लंबित था। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1992 में कांग्रेस सरकार ने 10 हजार रुपये आय सीमा निर्धारित की थी, जो 2009 तक नहीं बढ़ाई गई। हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की, जिससे लाभार्थियों की संख्या 17 लाख 98 हजार तक पहुंची और आज 20 लाख से अधिक बुजुर्ग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो शासन में पेंशन 200 रुपये और कांग्रेस के 10 वर्षों में 700 रुपये बढ़ी, जबकि हमारी सरकार ने 11 वर्षों में 2200 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की है।

राजगीर भ्रमण पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर्यटन विकास का किया अवलोकन

एजेंसी (हि.स.)
बिहारशरीफ

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को बिहार में राजगीर स्थित ग्लास ब्रिज, नेचर सफारी तथा जू सफारी परिसर का भ्रमण किया। उनके आगमन से राजगीर की सुरम्य वादियों और हरित प्राकृतिक वातावरण में विशेष उत्साह का माहौल देखा गया।

भ्रमण के दौरान मंत्री ने यहां की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सुव्यवस्थित पर्यटन व्यवस्था तथा जैव-विविधता संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजगीर ऐसा पर्यटन स्थल है जहां प्रकृति, रोमांच और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह स्थान देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से सफारी प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए पर्यटन को विकसित करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसे यहां प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। यह पहल स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता भी पैदा कर रही है। निरीक्षण के क्रम में मंत्री ने वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं, इको-टूरिज्म गतिविधियों, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों और आधुनिक पर्यटक प्रबंधन प्रणाली की जानकारी ली। इस दौरान जू सफारी के निदेशक राम सुन्दर एम ने उन्हें परिसर की संचालन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध तथा संरक्षण रणनीतियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

जापान के दौरे पर जाएंगे योगी, 600 किमी. रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में करेंगे सफर

सिटी दर्पण संवाददाता
लखनऊ

- मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को भारत-जापान सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा

जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव (मैग्नेटिक लेविटेशन) ट्रेन, जो चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का विशेष आकर्षण बनने जा रही है। मुख्यमंत्री अपने जापान प्रवास के दौरान इस हाईस्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे जिसमें 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर की वापसी होगी।

मैग्लेव ट्रेन को आधुनिक परिवहन का भविष्य माना जा रहा है। चुंबकीय तकनीक के कारण ट्रेन और ट्रैक के बीच प्रत्यक्ष संपर्क समाप्त हो जाता है, जिससे घर्षण लगभग शून्य हो जाता है। यही कारण है कि यह ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति हासिल करने में सक्षम है। जापान टोक्यो से नागोया के बीच मैग्लेव कॉरिडोर को वर्ष 2027 तक शुरू करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय आधे से भी कम रह जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह यात्रा केवल तकनीकी जिज्ञासा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन ढांचे के विस्तार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में पहले ही एक्सप्रेसवे, मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे परियोजनाओं के जरिए गतिशील इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। ऐसे में मैग्लेव जैसी भविष्य की तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव नीति निर्माण और दीर्घकालिक योजना के लिए उपयोगी माना जा रहा है।

जापानी विशेषज्ञों के अनुसार, इस ट्रेन में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट और अत्याधुनिक गाइडवे सिस्टम का उपयोग किया गया है, जो इसे उच्च गति के साथ स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करता है।

फिलहाल ट्रायल चरण में संचालित यह ट्रेन जापान की तकनीकी क्षमता और नवाचार की मिसाल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को भारत-जापान सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। हाईस्पीड रेल, स्मार्ट मोबिलिटी और सतत परिवहन के क्षेत्र में सहयोग से उत्तर प्रदेश समेत देश के परिवहन नेटवर्क को नई दिशा मिलने की संभावना जताई जा रही है।

स्टेडियम के निर्माण के लिए उप्र सरकार और इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. के बीच एमओयू हस्ताक्षरित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर जनपद गोरखपुर में अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार और इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुए। ज्ञातव्य है कि इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी सीएसआर निधि से इस स्टेडियम के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये का सहयोग प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह स्टेडियम केवल एक खेल संरचना नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की उभरती प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहुँचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम से इस क्षेत्र में खेल पर्यटन, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। गोरखपुर अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु इस वर्ष के बजट में आवश्यक प्राविधान किए गए हैं। यह स्टेडियम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के देश में खेल संस्कृति के विकास व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के विजन को आगे बढ़ाएगा। यह भारत की खेल सामर्थ्य को प्रदर्शित करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक-निजी सहभागिता का यह मॉडल राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने गोरखपुर अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में सीएसआर के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के लिए इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वाराणसी में भी एक अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निमार्णाधीन है, जिसे जून, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश में 'खेलो इण्डिया', 'फिट इण्डिया मूवमेण्ट' तथा 'सांसद खेलकूद प्रतियोगिता' जैसे अभियानों के माध्यम से खेल भावना और फिटनेस की संस्कृति को नई दिशा दी है। मेरठ में मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण तीव्रता से प्रगति पर है। इस वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने प्रत्येक मण्डल में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की व्यवस्था की है। इन्हें किसी एक विशेष खेल के लिए सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेज गति से 'स्पोर्ट्स पावर' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

वैश्विक समुदाय समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए आपस में हाथ मिलाए : राजनाथ

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

- रक्षा मंत्री ने विशाखापत्तनम में किया बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 'मिलन' का औपचारिक उद्घाटन

विशाखापत्तनम के पूर्वी तट पर चल रहे बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 'मिलन' में 74 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं, ताकि समुद्री जुड़ाव, सामूहिक सुरक्षा और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। अभ्यास का औपचारिक उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के कानूनी ढांचे को एक बड़े ग्लोबल नेवल आर्किटेक्चर के जरिए और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों और नेविगेशन की आजादी पर आधारित समुद्री व्यवस्था बनाना चाहता है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक भरोसेमंद विश्व-मित्र है, इस क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्टिव और भरोसेमंद भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे समुद्र में उभरती हुई मुश्किल और आपस में जुड़ी चुनौतियों से असरदार तरीके से निपटें और आपसी सम्मान और लेन-देन की भावना से काम करें। समय के साथ इंटरनेशनल शांति बनाने में नौसेना की भूमिका और बढ़ी है। पिछले कुछ दशकों में तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, जिससे इंटरनेशनल व्यापार और ट्रांसपोर्ट में भारी बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पानी को उन खतरनाक आतंकवादी गतिविधियों से बचाने की जरूरत है, जो इन इलाकों में पैर पसार रही हैं।

राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि पुराने खतरे, पाइरेसी, समुद्री आतंकवाद, गैर-कानूनी मछली पकड़ना, ट्रैफिकिंग, साइबर कमजोरियां और जरूरी सप्लाई चेन में रुकावट जैसी नई चुनौतियों के साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहा है, जिससे मानवीय और आपदा राहत ऑपरेशन ज्यादा बार-बार और मुश्किल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नेवी, चाहे कितनी भी काबिल क्यों न हो, अकेले इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती। उन्होंने एक सुरक्षित और ज्यादा सुरक्षित भविष्य पक्का करने के लिए नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

रक्षा मंत्री ने विशाखापत्तनम में नौ आसियान सदस्य देशों के नौसेना प्रमुखों और नौसेना प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। बैठक में भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र तरक्की के विजन पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह एक्सरसाइज 1995 में चार विदेशी नेवी के साथ शुरू हुई थी, जो अब 74 देशों के साथ होने वाले अपने अब तक के सबसे बड़े एडिशन तक पहुंच गई है। उन्होंने इंडो-पैसिफिक साझेदारों के बीच भरोसा और ऑपरेशनल जानकारी बढ़ाने में चीफ्स का कॉन्क्लेव और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के महत्व पर जोर दिया। चर्चा में मिलन के चल रहे बंदरगाह चरण पर भी बात हुई, जिसमें एंटी-सबमरीन वारफेयर, एयर डिफेंस और सर्च-एंड-रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे मुश्किल समुद्री ड्रिल पर फोकस किया गया।

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 'मिलन' की तुलना एक मैरीटाइम महाकुंभ से की, जिसमें दुनिया भर के मैरीटाइम प्रोफेशनल्स एक साथ आते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसा मैरीटाइम देश साफ तौर पर मानता है कि आज की मैरीटाइम चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई, जिन्हें सहयोग और साझेदारी से सुलझाया जा सकता है। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि मिलन के दौरान नौसेनाएं मुश्किल समुद्री युद्धाभ्यास, ड्रिल और एक्सरसाइज, प्रोफेशनल बातचीत और अच्छी बातचीत में शामिल होंगी।

घाटी में 70,000 नशेड़ियों में से 50,000 हेरोइन उपयोगकर्ता हैं: सरकार

जम्मू और कश्मीर मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों के खतरे का सामना कर रहा: जावेद रियाज

एजेंसी (हि.स.)

जम्मू

सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि कश्मीर में लगभग 70,000 लोग जिनमें अधिकतर युवा हैं नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं जिनमें से लगभग 50,000 हेरोइन उपयोगकर्ता हैं, जो अधिकतर नसों में इंजेक्शन के माध्यम से इसका सेवन करते हैं। विधायक जावेद रियाज द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहा कि जम्मू और कश्मीर, देश के कई अन्य क्षेत्रों की तरह मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों के खतरे का सामना कर रहा है जो गंभीर सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं पैदा कर रहा है।

सरकार ने कहा कि उसने इस समस्या से निपटने के लिए जागरूकता अभियान, निवारक उपाय, प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना और उपचार एवं पुनर्वास

सुविधाओं का विस्तार सहित बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर के 10 जिलों में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा 2022 में किए गए एक संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 70,000 लोग मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त पाए गए।

जवाब में आगे कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पुलिस द्वारा संचालित केंद्र शामिल हैं। अब तक जम्मू-कश्मीर के विभिन्न नशामुक्ति केंद्रों में लगभग 69,000 रोगियों को उपचार और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। सरकार ने सदन को यह भी सूचित किया कि नशामुक्ति केंद्रों (एटीएफ) के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ओपीडी/आईपीडी देखभाल, आपातकालीन सेवाएं और ओपिओइड प्रतिस्थापन थेरेपी (ओएसटी) सहित मुफ्त सेवाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में, 1,864 ग्राहक पंजीकृत हैं जिनमें से 358 सक्रिय लाभार्थी उपचार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति चिकित्सा क्लीनिक विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं जबकि स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन (एनएचएम), राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल (एनएपीडीडीआर) और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसी) अभियान चलाए जा रहे हैं।

वुलर झील में 1.35 लाख विलो के पेड़ काटे गए, 19 लाख पौधे लगाए गए: सरकार

जम्मू। सरकार ने गुरुवार को सदन को सूचित किया कि चरणबद्ध पुनर्स्थापन योजना के तहत वुलर झील और उसके आसपास लगभग 1.35 लाख विलो के पेड़ काटे गए हैं जबकि पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। विधायक इरशाद रसूल कर के प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री ने बताया कि वुलर झील के लिए व्यापक प्रबंधन कार्य योजना के तहत पहले चरण में 1.91 लाख विलो के पेड़ों को हटाने के लिए चिन्हित किया गया था। इनमें से लगभग 1.35 लाख पेड़ पहले ही हटाए जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई वनों की कटाई नहीं है बल्कि एक पर्यावरण प्रबंधन उपाय है जिसका उद्देश्य झील के प्राकृतिक आर्द्रभूमि स्वरूप को बहाल करना है। इसमें यह भी कहा गया कि योजना में अंधाधुंध कटाई का प्रावधान नहीं है बल्कि पारिस्थितिक लक्ष्यों के अनुरूप चुनिंदा और आवश्यकता-आधारित कटाई का प्रावधान है।

'जम्मू-कश्मीर की दिल्ली, अमृतसर और हरियाणा स्थित संपत्तियां अनाधिकृत नियंत्रण में हैं'

जम्मू। जम्मू और कश्मीर सरकार ने खुलासा किया है कि नई दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ में उसकी बहुमूल्य संपत्तियां उसके कब्जे में नहीं हैं बल्कि उन पर कब्जा है। इस खुलासे से सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी वित्तीय मूल्य की संपत्ति राज्य के नियंत्रण से कैसे निकल गई। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन के कटौती प्रस्ताव के लिखित जवाब में आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल विभाग के प्रभारी मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की 96 कनाल भूमि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के कब्जे में है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुस्तक 'कश्मीर-नैटिविटी रीगेन्ड' का किया विमोचन

एजेंसी (हि.स.)

जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि कश्मीरी पंडितों की पूरी गरिमा और सुरक्षा के साथ वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है। जम्मू कश्मीर 2019 से एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के सपनों और भाग्य को नष्ट करने की दुश्मन की भयावह साजिश को निर्णायक रूप से नष्ट कर दिया गया है। अथक प्रयास से इस भूमि का प्राचीन गौरव बहाल हुआ है और विकास को गति मिली है। उपराज्यपाल ने कहा कि बहुत जल्द, यह धरती आतंकवाद के संकट से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी।

वह प्रोफेसर अशोक कौल द्वारा लिखित पुस्तक कश्मीर-नैटिविटी रिगेन्ड के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। कश्मीर-नैटिविटी रीगेन्ड कश्मीरी पंडितों के पलायन की पड़ताल करता है और उन काले दिनों के आतंक और पैतृक जड़ों से विमुख होने की स्थायी तबाही को दर्शाता है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रोफेसर कौल की पुस्तक सिर्फ एक साहित्यिक प्रयास नहीं है, बल्कि दशकों से हमारी सामूहिक चेतना पर छाई चुप्पी को तोड़ने का प्रशंसनीय प्रयास है। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं कश्मीरी पंडित समुदाय की अदम्य भावना को सलाम करता हूं। प्रत्येक विस्थापित परिवार अपने भीतर कश्मीर का जीवित अंगारा लेकर आया है। संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों की भट्ठी में, उन्होंने दर्शन, आध्यात्मिकता, संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संरक्षित किया। पीड़ा में भी उन्होंने संभावनाओं की खोज की और सफलता के नए शिखर हासिल किए। उपराज्यपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2021 में, कश्मीरी पंडित समुदाय के घर और जमीनों को पुनः प्राप्त करने के लिए कश्मीरी प्रवासी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिन पर दूसरों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि दुनिया के सबसे गंभीर दुखों में से एक अपनी ही धरती पर अजनबी बनने की पीड़ा है। जम्मू-कश्मीर में ठीक यही हुआ था। 1989-90 में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की पीड़ा इतनी गहरी है कि समय का मरहम भी इसे शांत करने में विफल रहा है। उपराज्यपाल ने कहा, रात भर घर छोड़ने अपनी जड़ों से उखड़ने की पीड़ा विस्थापित परिवारों की रगों में कांटों की तरह आज भी है। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र ने सच्चाई को दफनाने की कोशिश की, लेकिन हम उन आतंकवादियों और उनके समर्थन नेटवर्क को कभी नहीं भूल सकते और कभी माफ नहीं कर सकते जिन्होंने आतंक का बीजारोपण किया और पीढ़ियों की आत्माओं पर हमला किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हजारों निर्दोष कश्मीरी मुसलमानों का खून भी बहाया है।

इस साल 6 विभूतियों को मिलेगा राष्ट्रीय एकात्मकता पुरस्कार

ऊना। हिमोत्कर्ष परिषद ने वर्ष 2025-26 के राष्ट्रीय एकात्मकता व हिमाचल श्री पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। यह जानकारी परिषद के मुख्य सलाहकार व सेवानिवृत एचएएस अधिकारी सतपाल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आगामी एक मार्च रविवार को एलजेएन हिमोत्कर्ष राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द के सभागार में परिषद के 52वें वार्षिक समारोह में उत्तर भारत की 6 विभूतियों को हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता व 3 विभूतियों व संस्थाओं को हिमोत्कर्ष हिमाचल श्री पुरस्कारों से अंलकृत किया जाएगा। सतपाल शर्मा ने बताया कि हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता पुरस्कार 2025-26 के तहत कांगड़ा जिला के शाहपुर से शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार, सेना मेडल को अमर शहीद कैप्टन अमोल कालिया स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता(शौर्य) पुरस्कार (मरणोपरांत) तथा तथा ऊना जिला के बाथू गांव से बीएसएफ से उपनिरीक्षक (से.नि.)व्यास देव को अमर शहीद कैप्टन अमोल कालिया स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता(राष्ट्र समर्पण एवं प्रेरणास्त्रोत)पुरस्कार,सिरमौर जिला के शिलाई से भारतीय महिला कबडडी टीम की उपकप्तान पुष्पा राणा को स्व.इंजीनियर मनमोहन सिंह कुंवर एवं प्रोमिला कंवर स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता (श्रेष्ठ युवा प्रतिभा खेल)पुरस्कार, हमीरपुर जिला से पंजाब केसरी टीवी हिमाचल के राज्य प्रमुख डा.संजीव शर्मा को अमर शहीद लाला जगत नारायण स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, बिलासपुर जिला के घुमारवी से संबधित डा.वाईएस परमार राजकीय चिक्तिसा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सहायक प्रौफेसर डा.अनिकेता शर्मा को स्व.इंजीनियर पंडित राम शर्मा स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता (उत्कृष्ट चिक्तिसक)पुरस्कार तथा हिमाचल मंडी जनकल्याण सभा (पंजीकृत)दिल्ली को स्व.डा.डीआर गर्ग स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता उत्कृष्ट नेत्र आयुर्विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सतपाल शर्मा ने बताया कि झारखंड राज्य न्यायिक सेवा के अंर्तगत जिला जज (वरीय न्यायिक सेवा)के पद पर चयनित ऊना जिला के डंगोली गांव के शिव करण राणा को स्व.रोशन लाल शर्मा स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचलश्री शान-ए-ऊना पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। चंडीगढ़ की समाज सेवी संस्था हिमाचल महासभा चंडीगढ़ को स्व.संतोष कंवर एवं स्व.कंवर हरिसिंह स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचलश्री (उत्कृष्ट समाज सेवी संस्था) पुरस्कार तथा बिलासपुर से साहित्यकार श्याम लाल शर्मा, सेवानिवृत संयुक्त सचिव हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला को राणा शमशेर सिंह स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचलश्री श्रेष्ठ लेखन, साहित्य एवं संस्कृति पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा।

जहर खाकर युवक की मौत, परिजनों ने धमकी और मारपीट का लगाया आरोप

शिमला। शिमला शहर में एक युवक की जहर खाने से हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों की धमकी और मारपीट से युवक इतना मानसिक दबाव में आ गया था कि उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना सदर में यह मामला राजू पुत्र निवासी कृष्णा नगर, शिमला की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार 7 फरवरी को दिन के समय कुछ परिचित लोग उस दुकान पर पहुंचे, जहां उसका भतीजा काम करता था। आरोप है कि वहां इन लोगों ने उसके भतीजे से झगड़ा किया, उसे धक्का दिया, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद युवक बुरी तरह डर गया और मानसिक तनाव में रहने लगा। परिजनों के अनुसार बढ़ते मानसिक दबाव के चलते युवक ने 17 फरवरी को जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

शिमला में नेपाली मजदूर की हत्या, नदी किनारे बंधे हाथ-पैर के साथ मिला शव

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

एक नेपाली मूल के मजदूर को मौत के घाट उतार बदमाशों ने उसका शव नदी किनारे फेंक दिया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने क्षत-विक्षत हालत में शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के हाथ-पैर बंधे हुए थे और सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है।

शिमला जिले के चिड़गांव क्षेत्र की उपतहसील जांगला के बडियारा में यह वारदात सामने आई। पुलिस थाना चिड़गांव में मामला दीपेंद्र पुत्र स्वर्गीय सुंदर लाल निवासी गांव दिसवानी, डाकघर कलोटी के बयान पर दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी की सुबह करीब आठ बजे वह अपने घर से बडियारा पुल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पब्बर नदी के किनारे खिलोचा नाले के पास उन्होंने बड़ी संख्या में कौवों

को मंडराते देखा।

संदेह होने पर जब दीपेंद्र पास पहुंचे तो एक व्यक्ति पीठ के बल पड़ा मिला। उन्होंने देखा कि मृतक के सिर के दाहिने हिस्से पर गहरी चोट थी। दोनों हाथ और पैर कपड़े से बंधे हुए थे और शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न था। सिर के पास काफी खून फैला हुआ था, जिससे हत्या की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने तुरंत 112 हेल्पलाइन पर सूचना दी और ग्राम पंचायत दिसवानी के प्रधान धर्मेंद्र को भी जानकारी दी। मृतक की पहचान सेती राम उर्फ राकेश प्रताप (उम्र करीब 46 वर्ष) निवासी जिला सल्याणी, नेपाल के रूप में हुई है। वह पिछले लगभग चार महीनों से बडियारा में जय लाल भंडारी के पास मजदूरी कर रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार शाम को मृतक को नेपाल मूल के कुछ अन्य लोगों के साथ देखा गया था। बताया जा रहा है कि उसने शाम के समय दो साथियों के साथ शराब का सेवन किया था, जिसके बाद वह लापता हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी प्रणव चौहान ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए व्यक्तियों की पहचान की जा रही है।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस ने कई अहम सुराग जुटाए हैं और संदिग्धों की तलाश के लिए टीमें जुटी हुई हैं।

संक्षिप्त-समाचार

नौशेरा में विदेशी पिस्तौल और मैगजीन के साथ एक गिरफ्तार

जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा इलाके में विदेशी पिस्तौल, मैगजीन और जिंदा कारतूसों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि नौशेरा पुलिस स्टेशन और सेना की एक संयुक्त गश्ती टीम ने रायपुर क्षेत्र में नौशेरा के सैर निवासी सचिन कुमार को पकड़ा। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान उसके पास से दो विदेशी पिस्तौल (तुर्की/चीन निर्मित), चार मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बिना किसी वैध दस्तावेज के बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि नौशेरा पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

जम्मू-कश्मीर में 36 लाख से अधिक परिवारों को अभी भी नल के पानी की सुविधा नहीं मिली है: मंत्री

जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 15.6 लाख घरों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं जबकि 3.61 लाख से अधिक घरों को अभी भी इन कनेक्शनों से वंचित रखा जाना बाकी है। सीपीआई (एम) विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति विभाग के प्रभारी मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि कुल 19,25,535 घरों में से 81 प्रतिशत से अधिक घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। राणा ने बताया कि जिलावार आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर और गांदरबल जिलों में क्रमशः 10,407 और 41,551 घरों को नल के पानी के कनेक्शन मिल चुके हैं। मंत्री ने बताया कि जम्मू जिले में 1,89,120 में से 1,26,170 घरों को नल कनेक्शन मिल चुका है जिससे 62,950 घर अभी भी बिना नल कनेक्शन के हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है।

शिक्षा मंत्री ने विधि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर भाजपा पर 'गुमराह' करने का आरोप लगाया

जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की नेता और कैबिनेट मंत्री सकीना इटू ने भाजपा पर जम्मू विधानसभा चुनाव के दौरान खोखले वादों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधानसभा के बाहर शिक्षा मंत्री ने भाजपा के चुनावी वादों और मौजूदा कार्यों के बीच के अंतर को उजागर किया। इटू ने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने यहां के लोगों को नौकरियों और उनके बैंक खातों में 10 लाख रुपये जमा करने का वादा किया था। उन्होंने हिंदू मुख्यमंत्री की बात की थी। आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनकी ये टिप्पणी क्षेत्र में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई है। मंत्री ने विपक्ष की इस मांग को जनता का ध्यान भटकाने का एक मात्र राजनीतिक हथकंडा बताया। उन्होंने सवाल किया कि अब उन्हें लगता है कि वे विधि विश्वविद्यालय की मांग करके जनता को शांत कर सकते हैं, लेकिन जनता समझदार है। विधि विश्वविद्यालय में क्या खास बात है? इसे कश्मीर, बारामूला, कुपवाड़ा या अनंतनाग में भी स्थापित किया जा सकता है। जम्मू के छात्र वहां पढ़ने जाएंगे। अब यह मुद्दा क्यों बन रहा है? मंत्री इटू ने वैष्णो देवी कॉलेज के छात्रों से जुड़े हालिया विवाद का हवाला देते हुए भाजपा के दोहरे मापदंड को रेखांकित किया। उन्होंने पूछा कि देखिए उन्होंने वैष्णो देवी कॉलेज के 50 छात्रों के साथ कैसा बर्ताव किया। अगर सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनके प्रवेश सुनिश्चित करने की गंभीरता नहीं होती तो उनके भविष्य का क्या होता? उन्होंने उन 50 छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं किया। अब, अगर मुस्लिम छात्र जम्मू के किसी विधि विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा? मंत्री इटू ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक हैं। विश्वविद्यालय कश्मीर में हो या बारामूला में, जम्मू के छात्र वहीं जाएंगे। वे समानता की बात तो करते रहते हैं। उनके कार्यों में समानता कहां है? शिक्षा मंत्री ने उपराज्यपाल (एलजी) के सीधे अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली कानून-व्यवस्था व्यवस्था पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अपने अधिकारों की मांग करने वाले लोगों के खिलाफ बल प्रयोग करता है। पुलिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वे उपराज्यपाल के अधीन हैं। वही लोगों की पिटाई करवाते हैं। लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है।

बार बार नशा तस्करी में शामिल महिला तीन माह के लिए निवारक हिरासत में

धर्मशाला। चिट्टे सही अन्य मादक पदार्थों की तस्करी की आरोपिता राजकुमारी को न्यायालय ने माह के लिए निवारक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं। उक्त आरोपी महिला बार बार नशा तस्करी में शामिल रही है। पालमपुर के विन्द्रावन निवासी, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के विरूद्ध थाना पालमपुर में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित चार मामले पंजीकृत हैं, जिनमें उसके कब्जे से चरस, गांजा तथा हेरोइन/चिट्टा जैसी नशीले पदार्थ की बरामदगी की गई थी। बार-बार गिरफ्तारी एवं जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपिता द्वारा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी की गतिविधियां जारी रखी गई। पुलिस एवं अन्य खुफिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपिता क्षेत्र में नशीले पदार्थों की आपूर्ति और वितरण में सक्रिय रूप से संलिप्त है, जिससे विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य एवं समाज की शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उसकी गतिविधियों को रोकना सार्वजनिक हित एवं जन-सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक पाया गया। जिस पर पुलिस द्वारा आरोपिता राजकुमारी के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत निवारक हिरासत के सम्बन्ध में प्रोपोजल तैयार करके उच्चाधिकारियों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था। इसी आधार पर आरोपिया राजकुमारी को तीन माह की अवधि के लिए जिला जेल कांगड़ा स्थित धर्मशाला में निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

सुक्खू सरकार केंद्र को कोसने के बजाय वित्तीय प्रबंधन सुधारे: जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार केंद्र से भरपूर सहयोग लेने के बावजूद लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है जबकि असली जरूरत प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को सुधारने की है।

गुरूवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (राजस्व घाटा अनुदान) को लेकर हो रही राजनीति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब यह ग्रांट हिमाचल को मिल रही थी, तब भी राज्य सरकार वित्तीय संकट का हवाला दे रही थी। उनके मुताबिक, यदि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद यह ग्रांट बंद हुई है, तो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी वित्तीय प्रबंधन करे और प्रदेश को आगे बढ़ाए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपनी नाकामियों का दोष केंद्र या पिछली सरकारों पर डालना समाधान नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि यदि वह हालात संभाल नहीं पा रही है तो जनता के सामने सच्चाई रखे। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सरकार राजस्व घाटा अनुदान पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर अड़ी रही। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान कई तथ्य गलत तरीके से पेश किए गए। विपक्ष ने जब इन तथ्यों को सुधारने के लिए बोलने का अवसर मांगा तो अनुमति नहीं दी गई, जिसके विरोध में भाजपा विधायकों को सदन के वेल में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश हितों के साथ खड़ी है और आगे भी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि आने वाले समय में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, गारंटियां पूरी करना कठिन हो सकता है और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व महंगाई भत्ते पर असर पड़ सकता है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय ठोस समाधान पर ध्यान देना चाहिए।

कालाअंब-त्रिलोकपुर मार्ग पर हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो की दर्दनाक मौत

नाहन। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के त्रिलोकपुर रोड पर स्थित रुचिरा इंडस्ट्री के सामने एक हृदयविदारक सड़क हादसा पेश आया है। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर के नीचे आने से दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे। रुचिरा इंडस्ट्री के समीप जब बाइक चालक ने आगे चल रहे एक ट्रैक्टर से पास लेने की कोशिश की, तो अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान बाइक पर पीछे बैठे दो लोग (एक पुरुष और एक महिला) सड़क पर गिर गए। इससे पहले कि वे संभल पाते, वे उसी ट्रैक्टर के पिछले टायर की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सूचना मिलते ही कालाअंब पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया। प्रारंभिक छानबीन में मृतकों के पास से कोई दस्तावेज, पहचान पत्र या मोबाइल बरामद नहीं हुआ है, जिससे उनकी शिनाख्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। एसपी सिरमौर निश्चित सिंह नेगी ने आधिकारिक तौर पर हादसे की पुष्टि की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी योगेश रोल्टा स्वयं घटनास्थल के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए हैं।

शिमला पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में दो तस्करों को किया गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

नशा तस्करी पर सख्ती दिखाते हुए जिला पुलिस शिमला ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों आरोपी पहले भी कई बार चिट्टा तस्करी के मामलों में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अवैध गतिविधियां बंद नहीं कीं। इसलिए पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार रोहड़ू क्षेत्र के गांव बेजोरी निवासी गगन भूषण को हिरासत में लेकर तीन महीने के लिए जेल भेजा गया है। गगन भूषण स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) 1985 के तहत कई मामलों में आरोपी रहा है और उसके कब्जे से अलग-अलग मामलों में हेरोइन/चिट्टा और चरस बरामद की जा चुकी है। रिकॉर्ड के मुताबिक गगन भूषण को पहली बार 25 मार्च 2019 को पुलिस थाना जुब्बल में दर्ज मामले में करीब 3.25 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा गया था। इसके बाद 17 जुलाई 2022 को रोहड़ू थाना में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में उससे क्रमशः करीब 51.33 ग्राम और 118.97 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वहीं 14 फरवरी 2023 को दर्ज एक अन्य मामले में उसके कब्जे से करीब 2.10 ग्राम चिट्टा और 113.78 ग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस का कहना है कि बार-बार गिरफ्तारी के बावजूद उसने तस्करी नहीं छोड़ी। इसी तरह पुलिस ने जुब्बल क्षेत्र के हाटकोटी निवासी नरेंद्र कुमार उर्फ नन्दु को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया है।

बेदखली के बाद भी नहीं छोड़ी वन विभाग की जमीन, दो सगे भाइयों पर एफआईआर

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। विभाग का आरोप है कि राजस्व विभाग द्वारा बेदखली के बावजूद दो लोग विवादित भूमि पर लगातार काम कर रहे हैं और जमीन खाली करने को तैयार नहीं हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह मामला महाशू वन विभाग के ब्लॉक फॉरेस्ट अधिकारी विक्रम सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना कोटखाई में दर्ज हुआ है। शिकायत में बताया गया है कि कोटखाई के महाशू निवासी दो सगे भाई बलवंत और दीपक ने महाशू में जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। बाद में राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया और भूमि वन विभाग को सौंप दी।

वन विभाग के अनुसार बेदखली के बाद विभाग के कर्मचारियों और वन रक्षकों ने मौके पर जाकर भूमि की सीमाओं पर स्थायी निशान लगाकर

कब्जा ले लिया था। इसके बावजूद आरोप है कि बलवंत और दीपक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं और चेतावनी के बाद भी उसी भूमि पर काम कर रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी कोटखाई के आदेश पर एक समिति गठित की गई। इस समिति ने 13 फरवरी को संबंधित खसरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिन प्लॉटों से बेदखली की गई थी, वहां सेब के पेड़ों की कटाई-छंटाई की गई थी, दवाइयों का छिड़काव किया गया था और कुछ पेड़ों के तनों पर चूना भी लगाया गया था। विभाग का कहना है कि यह काम उसी भूमि पर किया गया, जिसे पहले ही खाली करवाकर वन विभाग के हवाले किया जा चुका है।

मौसम

हिमाचल में बर्फबारी के बाद खुला मौसम

धूप खिली, विंटर सीजन में 28 फीसदी कम वर्षा

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बाद अब मौसम खुल गया है और गुरुवार को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप खिली रही। मैदानी और निचले इलाकों में कोहरे का कोई असर नहीं देखा गया। इससे लोगों को ठंड के बीच राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। इस विंटर सीजन में पहली जनवरी से अब तक सामान्य से 28 फीसदी कम बारिश हुई है।

मौसम केंद्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह कई शहरों के न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए। शिमला में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि

सुंदरनगर में 9.5, भुंतर में 7.0 और धर्मशाला में 9.7 डिग्री दर्ज किया गया। ऊना में 12.0 डिग्री, नाहन में 8.8 डिग्री, पालमपुर में 8.0 डिग्री और सोलन में 3.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। पर्यटन स्थलों की बात करें तो मनाली में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और यहां 1.0 मिलीमीटर वर्षा भी रिकॉर्ड की गई। कांगड़ा में 10.7 डिग्री, मंडी में 10.3 डिग्री और बिलासपुर में 12.5 डिग्री तापमान रहा। जुब्बड़हट्टी में 9.4 डिग्री, कसौली में 9.0 डिग्री, पांवटा साहिब में 14.0 डिग्री और देहरा गोपीपुर में 12.0 डिग्री दर्ज किया गया। सराहन में 5.6 डिग्री, सेओबाग में 5.5 डिग्री और बरठीं में 11.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे -3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में -2.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और अधिकांश स्थानों पर यह सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक अधिक रहा। वहीं अधिकतम तापमान में कई जगह गिरावट दर्ज की गई, हालांकि कुछ स्थानों पर यह सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा।

आने वाले दिनों के पूवार्नुमान के मुताबिक 19 से 22 फरवरी तक पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इस दौरान धूप खिली रहने की संभावना है और किसी तरह की बारिश या बर्फबारी का व्यापक अनुमान नहीं है। 23 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके बाद 24 और 25 फरवरी को मौसम के फिर से साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों के लिए राज्य में किसी प्रकार का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि बर्फबारी वाले ऊंचे क्षेत्रों में ठंड का असर बना हुआ है। राज्य के जनजातीय और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में तापमान अभी भी शून्य से नीचे बना हुआ है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एंव संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट न. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एंव 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्कः 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

सीएम ने कचरा प्रबंधन, ड्रेन सफाई और शिकायत निवारण पर तुरंत कार्रवाई करने के दिये निर्देश

मुख्यमंत्री ने सीएमजीजीए के साथ सफाई, कचरा प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधारों पर की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों से कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई को बेहतर बनाने के लिए उपायुक्तों के साथ मिलकर करें काम

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर निवास स्थान पर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिलों में सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, शिकायत निवारण सिस्टम को मजबूत करने और प्रशासनिक क्षमता में सुधार करनरे पर फोकस किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. यशपाल भी मौजूद रहे।सुशासन सहयोगियों ने मुख्यमंत्री को जिलों में जमीनी स्तर पर आने वाली मुख्य चुनौतियां और अपने-अपने जिलों में किए जा रहे नए तरीकों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कचरा अलग-अलग करने, नालों की सफाई, सीवरेज दुरूस्त करने, मैनपावर की कमी और लोगों में जागरूकता की कमी से जुड़े मुद्दों पर बात की।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग में शामिल हुए निगम आयुक्तों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने-अपने इलाकों में साफ सफाई के साथ कचरा प्रबंधन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नालों और सीवर लाइनों की नियमित रूप से सफाई करने और सीवरेज में आने वाली रुकावटों को तुरंत दूर करने तथा सफाई से जुड़े सभी लम्बित कामों को तेजी से पूरा करने की आवश्यकताओं पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम आयुक्त संबंधित जिलों में सीवरेज से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए नोडल ऑफिसर के रूप में काम करेंगे और उन्हें जनस्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि उनका जल्दी समाधान किया जा सके। जनता या शिकायत पोर्टल से मिली किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और समयबद्ध ढंग से शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सफाई और स्वच्छता पैरामीटर में औसत आधार पर कार्य कर रहे जिलों के निगम आयुक्तों के साथ वन-टू-वन बातचीत की और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुधार के उपाय करने और स्वच्छता पैमाने के साथ अपनी रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर दिखने वाले ऐसे सुधारों के परिणाम भी दिखने चाहिए जिनका आंकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक क्षमता के महत्व को दोहराते हुए अधिकारियों को कार्य के समय आने वाली रुकावटों से बचाव के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त स्टाफ को सही ढंग से तैनात करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि कोई भी फाइल बिना वजह पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए और सभी मामलों का आसान प्रक्रिया से तुरंत निपटाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की भागीदारी और व्यवहार में बदलाव को मजबूत बनाने के लिए सूचना एवं जागरूकता गतिविधियों को तेज किया जाए। उन्होंने सुशासन सहयोगियों को कचरा हॉटस्पॉट स्थानों की पहचान करने और ऐसे इलाकों में स्वच्छता के स्लोगन और जागरूकता संदेश लिखने के साथ-साथ विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिये।

हरियाणा में 12 लाख से ज्यादा लोगों का एचआईवी टेस्ट किया

पूरे राज्य में इलाज का नेटवर्क बढ़ाया गया

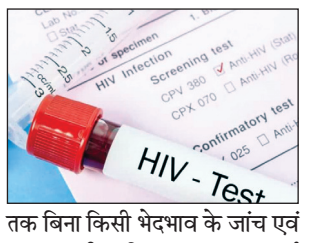

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा ने एचआईवी/एड्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेजी से बढ़ाते हुए चालू वित्तीय वर्ष में 12.40 लाख से अधिक लोगों का टेस्ट किया और राज्य के हर कोने में मरीजों तक पहुँचने के लिए उपचार के बुनियादी ढ़ाचें का विस्तार किया है।

उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच 12,40,205 लोगों की एचआईवी जांच की गई, जिनमें से 5,877 व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। राज्य में वर्तमान में 104 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (क्छ्ळ्उ) संचालित हैं, जिनमें फरीदाबाद में एक मोबाइल इकाई भी शामिल है। इन सभी केंद्रों पर निःशुल्क एवं गोपनीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस वित्त वर्ष में राज्य ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 5,65,830 गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच की गई, जिनमें से 613 महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव पाई गईं और उन्हें समय पर उपचार से जोड़ा गया, जो एचआईवी/एड्स के ऊर्ध्वाधर संचरण के उन्मूलन में मदद करता है। उपचार सुविधाओं के विस्तार के तहत राज्य में 24 एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (अफ्ळ) केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, हिसार, अंबाला और मेवात सहित प्रमुख जिलों में संचालित हैं। इनमें से 13 नए केंद्र मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए गए हैं, जिससे मरीजों को उन्नत उपचार सुविधाएं अपने निकट ही उपलब्ध हो रही हैं और उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही। इसके अतिरिक्त 5 फैसलिटी इंटीग्रेटेड एआरटी केंद्र तथा 4 लिंक एआरटी केंद्र भी कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्यभर में कुल 40,851 मरीज जीवन रक्षक उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

एचआईवी/एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों (ढछलत्क्ष) पर आर्थिक बोझ कम करने और उपचार अनुपालन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू की थी, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 2,250 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत 54.3 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। पंजीकृत मरीजों को निःशुल्क फॉलो-अप देखभाल तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (ढढढ) के माध्यम से अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत जांच सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। एचआईवी के अतिरिक्त राज्य यौन संचारित संक्रमणों (रळक) की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इसके लिए 31 नामित क्लीनिकों में निःशुल्क परामर्श, सिफिलिस जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

भारत रणभूमि दर्शन आज कुरुक्षेत्र में, नवीन जिन्दल करेंगे कारगिल योद्धाओं, वीर नारियों का सम्मान

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

नवीन जिन्दल फाउंडेशन 20 फरवरी शुक्रवार के दिन भारत रणभूमि दर्शन यात्रा सम्मान समारोह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आरके सदन में आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर देश के सैन्य गौरव, अमर शहीदों की पावन स्मृति और राष्ट्रीय एकता के अटूट संकल्प के साथ भारत रणभूमि दर्शन यात्रा में शामिल सेना के जांबाजों का भव्य अभिनंदन किया जाएगा।

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विजन और जिन्दल स्टील के सहयोग के द्वारा आयोजित राष्ट्रभक्ति के इस कार्यक्रम में रणभूमि से लौटे वीर जवानों, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले करगिल योद्धाओं और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता सांसद नवीन जिन्दल करेंगे। इस अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा, मेजर जनरल अरविंद यादव, कर्नल अश्विन, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मेजर जनरल (रि.) अशीम कोहली सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स और कारगिल विजय के योद्धा उपस्थित रहेंगे। यह यात्रा मंगलवार, 3 फरवरी को गुजरात के द्वारका से रवाना हुई थी। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के 200 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित इस अभियान का नेतृत्व भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा भारतीय नौसेना के गनर्स और सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से किया जा रहा है। कच्छ के रण और थार मरुस्थल की कठिन चुनौतियों को पार करते हुए 20 फरवरी को यह यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 21 फरवरी को दिल्ली में संपन्न होगी। गौरतलब है कि सांसद नवीन जिन्दल ने जनमानस को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जन जागरुकता और देश में विशाल तिरंगे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। विदित हो कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा पुराने एवं खंडित तिरंगों को एकत्रित कर उन्हें सम्मानपूर्वक रिसाइकिल करके नया स्वरूप देने का अभियान कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आरंभ किया गया है, जो कि बाद में पूरे देश में चलाया जाएगा। सांसद नवीन जिन्दल सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ तिरंगे के मान-सम्मान से जुड़ी यह विशेष मुहिम भी सांझा करेंगे।

पशुओं के पॉलिक्लिनिक एवं अस्पतालों के लिए आधुनिक मशीनें खरीदी जाएंगी : राणा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

गैस एनेस्थीसिया मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ब्लड टेस्ट उपकरण तथा 'बायो सेफ्टी लैब्स लेवल-2' स्थापित करने को मंजूरी

हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पशुओं के पॉलिक्लिनिक एवं अस्पतालों के लिए आधुनिक मशीनें खरीदी जाएंगी ताकि पशुपालकों के पशुधन का सस्ते में ईलाज हो सके। उन्होंने बताया कि आज हाई पावर्ड परचेज कमेटी में गैस एनेस्थीसिया मशीन , अल्ट्रासाउंड मशीन, ब्लड टेस्ट उपकरण तथा ₹बायो सेफ्टी लैब्स लेवल - 2₹ स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।

श्री राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमेटी के सदस्य हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा भी उपस्थित थे।

इनके अलावा , पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया , महानिदेशक डॉ प्रेम सिंह , संयुक्त निदेशक डॉ सुखदेव राठी , आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री पंकज , वित्त विभाग के विशेष सचिव डॉ जय इंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी में प्रदेश में पशुओं के ईलाज के लिए स्थापित पॉलीक्लिनिकों हेतु गैस एनेस्थीसिया मशीन खरीदने की मंजूरी दी गई है। इससे डॉक्टरों को पशुओं की सर्जरी करने में सुविधा होगी।

उन्होंने बताया कि पशुओं के इलाज (सर्जरी) में गैस एनेस्थीसिया मशीन इंजेक्टेबल की तुलना में अधिक सुरक्षित है, जो सटीक खुराक, तेज रिकवरी और बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करती है, जिससे पशुओं के हृदय और अन्य अंगों पर दबाव कम पड़ता है। यह प्रणाली दर्द प्रबंधन और छोटे-बड़े जानवरों के लिए अत्यंत विश्वसनीय है। उन्होंने आगे बताया कि हिसार , रायपुररानी तथा सोनीपत में ₹बायो सेफ्टी लैब्स लेवल - 2₹ स्थापित की जाएंगी। पशुओं में मध्यम जोखिम वाली बीमारियों की जांच के लिए उक्त लैब का उपयोग किया जाता है। यह लैब मानव/पशु स्वास्थ्य के लिए मध्यम-जोखिम वाले संक्रामक एजेंटों के परीक्षण के लिए होती है, इसमें विशेष पीपीई , बायोसेफ्टी कैबिनेट (इरउ), और कीटाणुशोधन (अ४३इङ्क्ष्५ी) की सुविधा होती है, जो श्वसन या त्वचा के संपर्क से संक्रमण रोकती है। उन्होंने बताया कि ₹बायो सेफ्टी लैब्स लेवल - 2₹ में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की जांच की जाती है ताकि इंसान बीमार पशुओं के सम्पर्क में आकर संक्रमित न हों और वे सुरक्षित रह सकें।

श्री श्याम सिंह राणा ने यह भी बताया कि पशुओं के ईलाज के लिए अल्ट्रासाउंड मशीने भी खरीदी जाएंगी। पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली ये अल्ट्रासाउंड मशीन जानवरों के आंतरिक अंगों, ऊतकों और गर्भावस्था का गैर-आक्रामक (ल्लङ्कल्ल७ल्ल५-२५ी) और विकिरण-मुक्त निदान करने के लिए एक अच्छी तकनीक है। यह तकनीक पालतू जानवरों (कुत्ते, बिल्ली) से लेकर पशुधन (गाय, भैंस, भेड़) में ट्यूमर, पेट की बीमारियों और प्रजनन संबंधी समस्याओं का सही पता लगाने में सहायक है। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार डॉक्टर को बीमार पशु के खून की जांच करवाने की जरुरत पड़ती है। अभी तक यह टेस्ट सुविधा लुवास यूनिवर्सिटी हिसार में ही उपलब्ध थी। आज की मीटिंग में पशुओं के खून टेस्ट के लिए उपकरण खरीदने की भी स्वीकृति दे दी गई है। अब सरकारी अस्पतालों में आने वाले बीमार पशुओं के ब्लड टेस्ट फ्री में किये जाएंगे और पशुओं का जल्द ईलाज करने में आसानी होगी।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसी भी पशुपालक या किसान का आर्थिक आधार पशु होते हैं जिनसे वे अपना परिवार चलाने के अलावा अतिरिक्त आमदनी कमाने का जरिया भी मानते हैं। राज्य सरकार अपने प्रदेश के पशु पालकों को समृद्ध बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है।

9 से 23 फरवरी तक मनाया जा रहा है स्मार्ट मीटर पखवाड़ा

चंडीगढ़। स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 9 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक सभी राज्यों में 'स्मार्ट मीटर पखवाड़ा' मनाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक यूएचबीवीएन के तीन शहरों करनाल, पानीपत और पंचकूला में लगभग पांच लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इन शहरों के उपभोक्ता अपने कनेक्शन को पोस्टपेड से प्रीपेड बिलिंग मोड में परिवर्तित कर बिजली शुल्क पर 5 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। 'स्मार्ट मीटर यूएचबीवीएन' मोबाइल एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस स्टोर, दोनों पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी दैनिक बिजली खपत पर निगरानी रख सकते हैं, प्रीपेड बिलिंग की स्थिति में क्रेडिट बैलेंस से संबंधित दैनिक अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं तथा स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान में यूएचबीवीएन में लगभग 31,600 उपभोक्ता मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी सहायता के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1912 या 1800-180-1550 पर संपर्क कर सकते हैं।

उपाध्यक्षा सुमन सैनी के आदेश पर प्रशासन ने शहजादपुर के बालक राम की 2 घंटे में की समस्या हल

सिटी दर्पण संवाददाता
लाडवा

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी के आदेश पर जिला प्रशासन ने गांव शहजादपुर के 100 प्रतिशत दिव्यांग बालक राम की समस्या का दो घंटे में हल किया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से गांव में टीम भेजकर दिव्यांग को बैटरी युक्त रिक्शा उपलब्ध करवाई गई।

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने वीरवार को गांव शहजादपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीण ने अपनी अपनी समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीण बालक राम ने शिकायत में बताया कि वो शत प्रतिशत दिव्यांग है और उसके पास हाथ चलित रिक्शा है, वो जिसको चलाने में असमर्थ है।

उपाध्यक्षा सुमन सैनी ने इस शिकायत पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा को भेजकर समस्या का समाधान करवाने के निर्देश दिए। इस समस्या पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने रेडक्रॉस सोसायटी सचिव को टीम के साथ बैटरी युक्त रिक्शा देकर गांव शहजादपुर में भेजा। गांव शहजादपुर निवासी बालक राम ने गांव में रिक्शा के साथ टीम को देखकर बड़ी खुशी जाहिर की।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर व्यापक चर्चा व राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा आवश्यकः सैलजा

देश के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्यों को रखा जाए

सिटी दर्पण संवाददाता
नई दिल्ली/सिरसा

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर देश में उठ रही चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते का मूल उद्देश्य देशहित, किसान-हित, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल स्वायत्तता की रक्षा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापार समझौते आर्थिक प्रगति के साधन होते हैं, किंतु वे राष्ट्रीय संप्रभुता या जनहित से समझौते की कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकते।

मीडिया को जारी एक बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि समझौते के विभिन्न प्रावधानों को देखते हुए किसानों, कृषि बाजार, ऊर्जा आयात व्यवस्था तथा डेटा सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्यों को रखा जाए ताकि किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों में किसी प्रकार की आशंका न रहे। उन्होंने विशेष रूप से कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि बड़े पैमाने पर शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है, तो इसका प्रभाव देश के मक्का, ज्वार, सोयाबीन तथा कपास उत्पादक किसानों पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि घरेलू किसानों की आय और बाजार संरक्षण के लिए क्या ठोस सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में कुमारी सैलजा ने कहा कि भारत जैसे बड़े ऊर्जा-आयातक देश के लिए कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता बनाए रखना रणनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता से पहले देश की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों, मूल्य स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता का व्यापक आकलन सार्वजनिक किया जाए। डिजिटल क्षेत्र और डेटा प्राइवेसी पर उठ रहे सवालों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल संप्रभुता और नागरिकों की निजता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि यदि व्यापार समझौते में इस क्षेत्र से जुड़े प्रावधान हैं तो उन्हें संसद और जनता के सामने स्पष्ट किया जाए।

कुमारी सैलजा ने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी संतुलित और समानता पर आधारित व्यापार सहयोग की समर्थक है, परंतु देशहित सर्वोपरि है।

हरियाणा के राज्यपाल घोष से प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने की शिष्टाचार भेंट

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने हरियाणा के माननीय राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. असीम कुमार घोष के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कुवि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने अपनी हाल ही में सम्पन्न जापान यात्रा के संबंध में माननीय राज्यपाल को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय, ओसाका विश्वविद्यालय, क्योटो विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय स्थित हैं तथा भविष्य में शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में आपसी सहयोग और शैक्षणिक आदान-प्रदान की व्यापक संभावनाएं हैं। वहीं भेंट के दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आगामी 1-2 महीनों में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह तथा संभावित मुख्य अतिथि के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।

हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान, विज्ञान, खेल सहित सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन विश्वविद्यालय को निरंतर प्राप्त होता रहेगा। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय को और अधिक उत्कृष्ट बनाने की दिशा में सतत प्रयास करने का आह्वान भी किया।

जनगणना

प्रदेश में जनगणना-2027 की बड़े पैमाने पर तैयारियां

पहली डिजिटल जनगणना के लिए हरियाणा तैयार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्य सचिव ने की एक दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता

हरियाणा में जनगणना-2027 को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना के सफल और समयबद्ध संचालन के लिए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों के एक दिवसीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि यह जनगणना केवल एक सांख्यिकीय कवायद भर नहीं, बल्कि आने वाले दशक की नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और आधारभूत संरचना के विकास की नींव है। साथ ही, यह राज्य की प्रशासनिक और तकनीकी दक्षता तथा समन्वय कौशल की भी परीक्षा है।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों और प्रधान जनगणना अधिकारियों को जनगणना की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं तथा उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाना है।

मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े नीति निर्माण एवं विकास योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों ने राज्य में कम बाल लिंगानुपात वाले जिलों की पहचान करने में मदद की और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप संभव हुआ। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि जनगणना में उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन, प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, जिले का पूर्ण कवरेज तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। मंडलायुक्त अपने अधीन जिलों की नियमित समीक्षा करें और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जनगणना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया में त्रुटि या लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण और संवेदनशीलता का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य के लिए जारी की गई धनराशि का समुचित उपयोग किया जाए। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इसके पहले चरण में 'मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना' 1 मई से 30 मई, 2026 तक की जाएगी। वर्ष 1966 में राज्य गठन के बाद से, हरियाणा के लिए यह छठी जनगणना होगी। परंपरागत प्रक्रिया से हटकर इस बार नागरिकों को स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प भी दिया जाएगा, जिसके लिए 16 अप्रैल, 2026 से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि नागरिक अपने विवरण पहले ही ऑनलाइन भर सकेंगे। जानकारी सबमिट करने के बाद उन्हें एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से एक विशिष्ट सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी प्राप्त होगी। इसके बाद जब गणनाकर्मी मौके पर आएंगे, तो वे केवल पहले से भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे, जिससे समय की बचत होगी और आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक श्री ललित जैन ने बताया कि आगामी जनगणना के अंतर्गत लगभग 50,000 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों को 203 ग्रामीण और शहरी चार्जों में कवर किया जाएगा। इस विशाल कार्य के लिए 50,000 से अधिक गणना कर्मी और 8,000 से अधिक पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। इनके प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर की चरणबद्ध प्रशिक्षण व्यवस्था अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गणना कर्मियों और पर्यवेक्षकों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने तथा कार्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार ने दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर 25,000 का मानदेय देने का निर्णय लिया है।

एनसीएलटी और कोर्ट आदेशों का अवश्य करें रजिस्ट्रेशन

एफसीआर डॉ. सुमिता मिश्रा ने जारी किए सख्त निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वितायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य के मण्डलायुक्त और उपायुक्तों को निर्देश दिये है कि वे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और न्यायालय के आदेशों का तय कानूनी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन अवश्य सुनिश्चित करें।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुख्य राजस्व अधिकारी, सब-रजिस्ट्रार और संयुक्त सब-रजिस्ट्रार को नेशनल कम्पनी ट्रिब्यूनल और कोर्ट के आदेशों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में 13 नवंबर, 2013 को पहले के जारी निर्देशों और 22 नवंबर 2017 की अधिसूचना का पालन करना हैं।

उन्होंने बताया कि नेशनल कम्पनी ट्रिब्यूनल के आदेशों से जुड़े मामलों में इंडियन स्टैम्प एक्ट, 1899 के शेड्यूल 1-ए के आर्टिकल 23-ए के तहत 1.5 प्रतिशत की दर से स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा लिमिट 7.5 करोड़ रुपये है। इसी तरह नॉन-बोनाफाइड कोर्ट के आदेश भी इसी नियम के तहत आते हैं। इन कानूनी नियमों का पालन करके राज्य के खजाने पर स्टैम्प ड्यूटी राजस्व बढाया जाना है।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि इंडियन स्टैम्प एक्ट के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और ऐसे मामलों में बिना किसी छूट के सही स्टैम्प ड्यूटी का आंकलन और रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति के ट्रांसफर से जुड़े कई मामलों में न्यायालय द्वारा जारी स्टे ऑर्डर सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचने पर जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चूक न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। इसलिए, सर्कल राजस्व अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है कि किसी भी न्यायालय से मिला कोई भी स्टे ऑर्डर तुरंत रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखाई दे।

वित्तायुक्त राजस्व ने सभी उपमण्डलायुक्तों और उपायुक्तों से कहा है कि वे अपने अधीन सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दें कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कोई भी चूक होने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।

संपादकीय

भुखमरी से जंग में भारत की एंट्री – मानवीय सहयोग के लिए लिखा नया अध्याय

वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा और भूख से जुड़ी चुनौतियाँ लगातार गहराती जा रही हैं, और इसी संदर्भ में हाल में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है, जिसमें भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आधारशिला मानी जाने वाली संस्था फूड कार्पो-रेशन ऑफ इंडिया और संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी ब्लर्ड फूड प्रोग्राम के बीच चावल की आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ है। यह पहल केवल संस्थागत सहयोग का मामला नहीं है, बल्कि इसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा ढाँचे में भारत की बढ़ती भूमिका के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भूख और कुपोषण की समस्या आज भी दुनिया के कई क्षेत्रों में गंभीर सामाजिक-आर्थिक संकट का कारण बनी हुई है, ऐसे में खाद्यान्न आपूर्ति से जुड़ा यह सहयोग व्यापक मानवीय और रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस समझौते का मूल उद्देश्य उन देशों और क्षेत्रों तक खाद्यान्न पहुँचाना है जहाँ खाद्य संकट गहराता जा रहा है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय संघर्ष, महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियाँ और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएँ जैसी स्थितियों ने लाखों लोगों को खाद्य असुरक्षा की स्थिति में धकेल दिया है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के आकलन लगातार इस ओर संकेत करते रहे हैं कि कई विकासशील और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भोजन तक पहुँच अब भी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। ऐसे समय में भारत जैसे कृषि उत्पादन क्षमता वाले देश की भागीदारी न केवल राहत पहुँचाने में सहायक है, बल्कि यह बहुपक्षीय सहयोग की भावना को भी मजबूत बनाती है। भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में दशकों की नीति, निवेश और तकनीकी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की है। हरित क्रांति के बाद कृषि ढाँचे में हुए परिवर्तन, उन्नत बीज, सिंचाई विस्तार और सरकारी खरीद प्रणाली ने देश को अधिशेष भंडारण की स्थिति में पहुँचाया। इसी ढाँचे का संचालन खाद्य निगम करता है, जो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर राष्ट्रीय भंडारण बनाए रखता है। इस तंत्र का मूल उद्देश्य घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किंतु यही क्षमता अब अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रमों में भी उपयोगी साबित हो रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय संसाधन और वैश्विक जिम्मेदारी एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं। समझौते के तहत उपलब्ध कराया जाने वाला चावल उन क्षेत्रों में भेजा जाएगा जहाँ आपातकालीन सहायता की आवश्यकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम लंबे समय से युद्धग्रस्त इलाकों, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों और आर्थिक संकट झेल रहे समुदायों में भोजन वितरण का कार्य करता रहा है। भारत से मिलने वाली आपूर्ति इन अभियानों की निरंतरता को सुदृढ़ बनाएगी। इससे न केवल खाद्यान्न वितरण का दायरा बढ़ेगा बल्कि उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी जिनके लिए रोजाना का भोजन जुटाना भी कठिन बना हुआ है। इस पहल को भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में भारत ने मानवीय सहायता और विकास सहयोग को अपनी वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। स्वास्थ्य संकट के दौरान दवाइयों और टीकों की आपूर्ति, आपदा राहत अभियानों में सहयोग और अब खाद्यान्न सहायता–ये सभी कदम उस नीति की निरंतरता को दर्शाते हैं जिसमें वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझेदारी को महत्व दिया गया है। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और सहायक साझेदार के रूप में उभरती है, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह के समझौते बहुआयामी प्रभाव डाल सकते हैं। अधिशेष भंडार का उपयोग कर भंडारण लागत और संसाधनों के प्रबंधन को संतुलित किया जा सकता है। साथ ही किसानों के लिए स्थिर खरीद प्रणाली बनी रहती है, जिससे कृषि क्षेत्र में विश्वास और निरंतरता कायम रहती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न आपूर्ति में भागीदारी से भारत की विश्वसनीयता भी बढ़ती है, जो भविष्य में व्यापार और सहयोग के नए अवसर खोल सकती है। यह नीति संतुलन का उदाहरण है जहाँ घरेलू हितों की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। हालाँकि, इस तरह की पहल के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं। वैश्विक सहायता में योगदान देते समय घरेलू आवश्यकताओं का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अनिश्चितताएँ, उत्पादन में उतार-चढ़ाव और भंडारण की सीमाएँ नीति निमार्ताओं के सामने लगातार प्रश्न खड़े करती हैं। इसलिए इस तरह के समझौतों को दीर्घकालिक योजना, जोखिम आकलन और पारदर्शी प्रबंधन के साथ लागू करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक भूख की समस्या केवल खाद्यान्न की कमी तक सीमित नहीं है। यह गरीबी, असमानता, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता और राजनीतिक अस्थिरता जैसे व्यापक कारकों से जुड़ी है। इसलिए चावल आपूर्ति जैसे कदम राहत अवश्य प्रदान करते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए बहुआयामी विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता बनी रहती है। यह पहल तब अधिक प्रभावी हो सकती है जब इसे स्थानीय कृषि विकास, पोषण योजनाओं और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों के साथ जोड़ा जाए। फिर भी, इस सहयोग का प्रतीकात्मक महत्व अत्यंत बड़ा है। यह अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और साझा जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब राष्ट्रीय संस्थाएँ और वैश्विक एजेंसियाँ मिलकर काम करती हैं, तो जटिल मानवीय संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग का संदेश यह भी दशार्ता है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अंततः, चावल आपूर्ति से जुड़ा यह समझौता केवल संसाधनों के हस्तांतरण की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सहयोग और मानवीय संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह भारत के लिए अवसर भी है और जिम्मेदारी भी–अवसर अपनी उत्पादन क्षमता और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का, तथा जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने का कि यह सहयोग संतुलित और सतत बना रहे। यदि इसे दूरदर्शिता और समन्वय के साथ आगे बढ़ाया गया, तो यह वैश्विक भूख से लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में याद किया जा सकता है।

न्याय बने विकास की कसौटी

योगेश कुमार गोयल (हि.स)

किसी भी समाज की सच्ची प्रगति उसकी ऊंची इमारतों या तेज आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह अपने सबसे कमजोर, वंचित और हाशिए पर खड़े नागरिकों को कितना न्यायपूर्ण, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। 20 फरवरी को मनाया जाने वाला सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मानव सभ्यता की उस मूल चेतना का प्रतीक है, जिसके बिना न तो शांति संभव है और न ही टिकाऊ विकास। इस दिवस की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, असमानता और भेदभाव जैसी जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए देशों के बीच साझा प्रतिबद्धता को मजबूती मिल सके।

वर्ष 2026 में सामाजिक न्याय का विश्व दिवस की थीम है ह्यसमावेशन को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटनाह्न। यह थीम स्पष्ट करती है कि असमानताओं को कम करने के लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि विकास की प्रक्रिया में समाज के हर वर्ग की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो। समावेशन का अर्थ केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उन लोगों की आवाज को स्थान देना है, जो अब तक हाशिए पर रहे हैं। जब तक नीतियां केवल केंद्रों में बनती रहेंगी और उनका प्रभाव जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक सामाजिक न्याय एक अधूरा लक्ष्य बना रहेगा।

यह दिवस विशेष प्रासंगिकता रखता है क्योंकि आज की दुनिया एक गहरे संक्रमणकाल से गुजर रही है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक तनावों ने आर्थिक व सामाजिक ढ़ांचों को तेजी से बदला है। इन बदलावों का लाभ जहां कुछ सीमित वर्गों तक सिमट गया है, वहीं बड़ी आबादी, विशेषकर गरीब, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, महिलाएं, प्रवासी, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक समुदाय और अधिक असुरक्षित होती जा रही है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय केवल नैतिक आदर्श नहीं, नीति और शासन की अनिवार्य प्राथमिकता बन चुका है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा अवसरों, संसाधनों और अधिकारों के निष्पक्ष वितरण से जुड़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी को समान परिणाम मिले बल्कि यह है कि सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और कानूनी सुरक्षा तक समान पहुंच इसके मूल स्तंभ हैं। जब किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान या आर्थिक स्थिति से तय होने लगे, तब यह स्पष्ट संकेत होता है कि समाज में न्याय का संतुलन बिगड़ चुका है। आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। एक ओर अत्यधिक संपन्न वर्ग है, जिसके पास संसाधनों और अवसरों की प्रचुरता है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी, असुरक्षित रोजगार और कम वेतन ने विशेष रूप से युवाओं के सामने गंभीर संकट खड़े कर दिए हैं। इसी संदर्भ में सम्मानजनक कार्य और मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता सामने आती है। पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी सहायता और खाद्य सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं केवल कल्याणकारी योजनाएं नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता और भरोसे की आधारशिला हैं।

भारत में सामाजिक न्याय का विचार गहरे संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा है। संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है जबकि मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत असमानताओं को कम करने और कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से आरक्षण नीति, सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश तथा कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बावजूद इसके, क्षेत्रीय असमानताएं, शहरी-ग्रामीण विभाजन, डिजिटल डिवाइड और लैंगिक विषमता जैसी चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं।

सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है कि क्या हमारी नीतियां अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, क्या शिक्षा और रोजगार के अवसर वास्तव में समान हैं और क्या विकास का लाभ संतुलित रूप से बंट रहा है? यह दिवस यह भी याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी एक देश या सरकार की नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग और सामूहिक प्रयास की मांग करती है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस 2026 इस सत्य को दोहराता है कि सच्ची प्रगति तभी संभव है, जब कोई भी पीछे न छूटे। समावेशन और सशक्तिकरण केवल शब्द नहीं बल्कि रोजमर्रा के निर्णयों, नीतियों और सामाजिक व्यवहारों में उतारने योग्य जिम्मेदारी हैं। जब हर व्यक्ति को समान गरिमा, अवसर और सुरक्षा मिलती है, तभी न्याय कागजों से निकलकर जीवन की वास्तविकता बनता है और एक अधिक मानवीय, समावेशी तथा न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण संभव हो पाता है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेषः आज दिन कुछ उलझनों के साथ गुजर सकता है और निर्णय लेने में असमंजस बना रहेगा। समय का सही उपयोग न होने से निराशा हो सकती है। भाई-बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः नौकरीपेशा लोगों के लिए आय में सुधार के संकेत हैं। यदि नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और प्रियजनों का मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा। संतान अपने प्रदर्शन से गर्व का अवसर दे सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सजग रहने की आवश्यकता है। दांपत्य जीवन में भावनात्मक निकटता बनी रहेगी, लेकिन दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएँ रखने से बचें। आज अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें। संतान से जुड़े मामलों को लेकर सोच-विचार कर सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः आज प्रतिक्रिया देने में संयम बरतना आवश्यक है। धार्मिक या वैचारिक उलझनें मन में पैदा हो सकती हैं। संपत्ति से जुड़े मुद्दे जटिल हो सकते हैं और कार्यस्थल पर कठिन जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। यात्रा से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, साथ ही पुरानी भूलों का असर सामने आ सकता है। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कटु भाषा से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। यदि पहले से कोई परेशानी है तो चिकित्सकीय सलाह लें। सिरदर्द या बुखार जैसी समस्या परेशान कर सकती है। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः घर में शांति और संतोष का माहौल रहेगा। योजनाएँ उम्मीद के अनुरूप आगे बढ़ेंगी और व्यापारिक समझौते फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक लाभ की संभावना और अच्छी खबर से उत्साह बढ़ेगा। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः विवाह योग्य लोगों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विदेशी संपर्क लाभ पहुंचा सकते हैं। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। गले या कफ से जुड़ी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थी करियर को लेकर मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः संतान के व्यवहार से असंतोष हो सकता है और आर्थिक चिंताएँ मन को अस्थिर कर सकती हैं। भाग्य को दोष देने के बजाय चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करें। जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। *(सिटी दर्पण)*

धनुः जीवनसाथी के साथ भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए बातचीत से समाधान निकालें। कामकाज में मन कम लगेगा और घर में किसी उपकरण की खराबी परेशानी दे सकती है। जरूरी काम अधूरे रह जाने की आशंका है, इसलिए प्राथमिकता तय करें। *(सिटी दर्पण)*

मकरः आकर्षण और सामाजिक संपर्क बढ़ सकते हैं। व्यापार में अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिलेंगे, हालांकि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को चुनौतियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। अधीनस्थों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः महत्वपूर्ण कार्य में रुकावट से मन खिन्न हो सकता है। बच्चों या आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताना राहत देगा। सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखें और सत्यनिष्ठ व्यवहार अपनाएँ, अन्यथा प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मीनः आप अपने दायित्वों के प्रति सजग और संवेदनशील रहेंगे। सोशल मीडिया या प्रचार गतिविधियों में सक्रियता बढ़ सकती है। मानसिक दृढ़ता आपको आगे बढ़ाएगी। कमीशन आधारित कार्यों से लाभ के संकेत हैं। नए समझौते बन सकते हैं, लेकिन शुरूआत में देरी संभव है। *(सिटी दर्पण)*

रोबोडॉग प्रकरणः प्रमाणन की होड़ में दम तोड़ती अकादमिक गुणवत्ता

डॉ. प्रियंका सौरभ

गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रोबोडॉग के प्रदर्शन से जुड़ा हालिया विवाद सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बना। सतह पर यह मामला उपयुक्तता, प्राथमिकताओं या कैंपस संस्कृति से जुड़ा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से पनप रहे गहरे और संरचनात्मक संकट का केवल एक लक्षण है। समस्या रोबोडॉग नहीं है। समस्या यह है कि हमारे विश्वविद्यालय धीरे-धीरे क्या बनते चले गए हैं।

पिछले दो दशकों में भारत में उच्च शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। निजी विश्वविद्यालयों, स्ववित्तपोषित कॉलेजों और डिग्री संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस विस्तार को अक्सर शिक्षा तक पहुँच बढ़ने और जनसांख्यिकीय लाभ के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब यह विस्तार समानांतर नियमन, अकादमिक कठोरता और जवाबदेही के बिना हुआ तो इसकी कीमत गुणवत्ता को चुकानी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि मात्रा बढ़ी पर गुणवत्ता लगातार गिरती चली गई।

आज देश के अधिकांश-हालाँकि सभी नहीं–निजी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज शिक्षा के केंद्र कम और डिग्री वितरण केंद्र अधिक बन गए हैं। शिक्षा एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लेन-देन बनती जा रही है- पैसे के बदले डिग्री। उपस्थिति, अकादमिक भागीदारी, प्रयोगशाला कार्य और बौद्धिक अनुशासन जैसी बातें अब अनिवार्य नहीं रहीं, बल्कि समझौते के दायरे में आ गई हैं। जो कभी उच्च शिक्षा में गैर-समझौतावादी हुआ करता था, वह अब लचीला, कमजोर और विकृत हो चुका है।

यह गिरावट विशेष रूप से उन विषयों में चिंताजनक है जहाँ कठोरता अनिवार्य है। सैद्धांतिक पढ़ाई का कमजोर होना एक बात है, लेकिन विज्ञान शिक्षा का खोखला हो जाना कहीं अधिक गंभीर है। आज स्थिति यह है कि छात्र बिना नियमित कक्षाओं में गए और बिना प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण लिए विज्ञान जैसे विषयों में स्नातक और परास्नातक डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं। प्रयोगात्मक कार्य- जो कभी वैज्ञानिक प्रशिक्षण की रीढ़ हुआ करता था–अब औपचारिकता बनकर रह गया है। डिग्रियाँ तो दी जा रही हैं लेकिन दक्षता सुनिश्चित नहीं की जा रही।

इस खोखलेपन के परिणाम तब स्पष्ट होते हैं जब छात्र नौकरी के लिए सामने आते हैं। रसायन विज्ञान में परास्नातक छात्र बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाएँ नहीं समझ पाता। कॉमर्स स्नातक डेबिट और क्रेडिट की मूल अवधारणा स्पष्ट नहीं कर पाता। प्रबंधन की डिग्री रखने वाला छात्र समस्या-समाधान और आलोचनात्मक सोच में कमजोर दिखाई देता है। ये कोई इक्का-दुक्का उदाहरण नहीं बल्कि उद्योग जगत द्वारा बार-बार देखी जा रही सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं।

स्वाभाविक रूप से इससे छात्रों और अभिभावकों में निराशा पैदा होती है। वर्षों की पढ़ाई और भारी आर्थिक निवेश के बावजूद जब रोजगार नहीं मिलता तो सवाल उठते हैं। माता-पिता यह पूछने में बिल्कुल सही होते हैं कि पढ़ाई के बाद भी बच्चा बेरोजगार क्यों है। अक्सर इस असंतोष का निशाना सरकार बनती है, जिस पर रोजगार सृजन न कर पाने का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि रोजगार सृजन एक नीतिगत चुनौती है लेकिन यह विमर्श एक असहज सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है कि बड़ी संख्या में स्नातक वास्तव में रोजगार योग्य ही नहीं हैं।

यहीं से मूल प्रश्न जन्म लेता है। यदि छात्रों में आवश्यक ज्ञान और कौशल नहीं है तो उन्हें योग्य घोषित करने वाली डिग्रियाँ उन्हें कैसे मिल गईं? ऐसी संस्थाओं को बिना अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित किए प्रमाणपत्र बाँटने की अनुमति किसने दी? इसका उत्तर हमें उच्च शिक्षा के नियामक ढाँचे में मिलता है।

भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख कई मंत्रालयों, विभागों और नियामक संस्थाओं द्वारा की जाती है, जिनका घोषित उद्देश्य मानकों की रक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अकादमिक ईमानदारी बनाए रखना है। मान्यता प्रणालियाँ, निरीक्षण, मूल्यांकन और अकादमिक ऑडिट इसी उद्देश्य से बनाए गए थे। लेकिन व्यवहार में ये प्रक्रियाएँ अक्सर वास्तविक मूल्यांकन की बजाय औपचारिक अनुष्ठान बनकर रह गई हैं।

निरीक्षण प्रायः पूर्व निर्धारित होते हैं। दस्तावेज औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सजाए जाते हैं। इमारतों और बुनियादी ढाँचे को शिक्षण गुणवत्ता पर प्राथमिकता दी जाती है। अनुपालन को सीखने के परिणामों से ऊपर रखा जाता है। छात्रों का वास्तविक अकादमिक अनुभव, शिक्षण की गुणवत्ता, परीक्षा की कठोरता और जिज्ञासा की संस्कृति- इन पर गंभीर और निरंतर निगरानी शायद ही होती है। नतीजतन, संस्थान शिक्षा सुधारने के बजाय नियामकों को ह्लमैनेजह्न करना सीख लेते हैं।

इस नियामक शिथिलता ने एक दुष्चक्र को जन्म दिया है- संस्थान न्यूनतम अकादमिक जवाबदेही के साथ चलते रहते हैं, नियामक निगरानी का आभास बनाए रखते हैं और डिग्रियाँ लगातार जारी होती रहती हैं। इस व्यवस्था की कीमत न तो संस्थान चुकाते हैं, न ही नियामक बल्कि छात्र, नियोक्ता और समाज चुकाता है।

विडंबना यह है कि एक ओर उद्योग जगत योग्य मानव संसाधन की कमी की शिकायत करता है, वहीं दूसरी ओर देश शिक्षित बेरोजगारी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। यह कोई विरोधाभास नहीं बल्कि उस व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है जहाँ प्रमाणपत्र को क्षमता से ऊपर रखा गया है। कंपनियाँ नए कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने पर भारी खर्च करने को मजबूर हैं, जबकि युवा पेशेवर आत्मविश्वास की कमी और करियर ठहराव से जूझते हैं।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार वे ईमानदार और प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो अक्सर विकल्पों की कमी या भ्रामक ब्रांडिंग के कारण औसत संस्थानों में दाखिला ले लेते हैं। वे मेहनत करते हैं, सीखना चाहते हैं लेकिन अंततः उन्हें अपनी काबिलियत से ज्यादा अपनी मार्कशीट पर दर्ज संस्थान के नाम का बोझ उठाना पड़ता है। उनकी व्यक्तिगत योग्यता संस्थागत विश्वसनीयता की कमी में दब जाती है। यह केवल अन्याय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की बबार्दी है।

यह स्वीकार करना होगा कि भारत में आज भी कुछ उच्च-गुणवत्ता वाले संस्थान मौजूद हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन वे अपवाद हैं, नियम नहीं। उल्लेखनीय है कि बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा आज भी अपेक्षाकृत अधिक संरचित और नियंत्रित है। जैसे ही छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, निगरानी ढीली पड़ जाती है और अपेक्षाएँ धुंधली हो जाती हैं।

यदि इस प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम गंभीर होंगे। डिग्रियों का सामाजिक और आर्थिक मूल्य घटेगा। उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक विश्वास कमजोर होगा। योग्यता और औसतपन के बीच का अंतर और अधिक अस्पष्ट होता जाएगा। हर गली में विश्वविद्यालय जैसे वाक्य व्यंग्य नहीं बल्कि यथार्थ का वर्णन बन जाएंगे–जहाँ विश्वविद्यालय तो हर जगह होंगे, पर शिक्षा नहीं।

अब सुधार का समय है और यह सुधार ईमानदार और कठोर होना चाहिए। नियामक संस्थाओं को बॉक्स-टिकिंग से आगे जाकर परिणाम आधारित, पारदर्शी और अप्रत्याशित मूल्यांकन अपनाना होगा। शिक्षण की गुणवत्ता, सीखने के परिणाम, छात्र सहभागिता और मूल्यांकन की ईमानदारी को इमारतों और विज्ञापनों से ऊपर रखना होगा।

संस्थानों की जवाबदेही तय करनी होगी। जो कॉलेज और विश्वविद्यालय लगातार अकादमिक रूप से असफल हो रहे हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए- सीटों में कटौती, पाठ्यक्रम निलंबन या मान्यता रद्द करने तक। उच्च शिक्षा ऐसा व्यवसाय नहीं हो सकता जहाँ असफलता की कोई कीमत न चुकानी पड़े।

छात्रों और अभिभावकों को भी अधिक सजग होना होगा। केवल मार्केटिंग, बुनियादी ढाँचे और ब्रांडिंग के आधार पर निर्णय लेना भविष्य के साथ समझौता है। शिक्षा कोई साधारण खरीद नहीं बल्कि बौद्धिक और व्यावसायिक विकास में निवेश है और गलत निर्णयों के दूरगामी परिणाम होते हैं।

अंततः, उच्च शिक्षा का उद्देश्य डिग्री बाँटना नहीं बल्कि सोचने-समझने वाले, सक्षम और ज़िम्मेदार नागरिक तैयार करना है। जब तक यह मूल उद्देश्य पुनः स्थापित नहीं होता, तब तक रोबोडॉग जैसे विवाद आते रहेंगे- कुछ समय के लिए शोर मचाएँगे और फिर शांत हो जाएँगे, जबकि असली संकट जस का तस बना रहेगा। हमें सजावटी सुधार नहीं, बल्कि प्रणालीगत आत्ममंथन चाहिए। क्योंकि शिक्षा का संकट केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता, वह चुपचाप राष्ट्र का भविष्य गढ़ता है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

गहरे संदेश देती 'कंजकः द गर्ल विदाउट अ नेम'

विवेक शुक्ला (हि.स)

हिंदुओं के लिए नवरात्रि सिर्फ. त्योहार नहीं, एक गहरी भावना है जो हमारी संस्कृति में बसी हुई है। साल में दो बार मनाया जाने वाला यह त्योहार अष्टमी या नवमी पर कंजक या कन्या पूजन के साथ खत्म होता है। इस दिन घर में नौ छोटी लड़कियों और एक लड़के (जिसे अक्सर लोंकड़ा कहते हैं) को बुलाया जाता है और उन्हें मां दुर्गा का जीवंत रूप मानकर पूजा जाता है। उन्हें पूढ़ी, हलवा, चना खिलाया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और उनके पैर छुए जाते हैं। यह रस्म शुद्धता, भक्ति और स्त्री शक्ति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है।

यह रस्म बहुत पवित्र और प्यारी है, लेकिन इसमें कुछ सामाजिक बारीकियां और रोजमर्रा की मुश्किलें भी छिपी हैं। इन्हीं बातों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया

है फिल्म 'कंजकः द गर्ल विदाउट अ नेम' में। यह फिल्म सच्चिदानंद जोशी की कहानी पर आधारित है। राहुल यादव ने इसे बहुत संवेदनशीलता से निर्देशित किया है। यह हाल ही में रिलीज हुई एक छोटी लेकिन गहरी छाप छोड़ने वाली कहानी है, जो दिल्ली के एक मध्यमवर्गीय घर में दुर्गा पूजा के दौरान घटित होती है। पूजा से पहले का हंगामा कहानी की मुख्य किरदार हैं एक सम्मानित और धार्मिक महिला, जिन्हें सब प्यार से 'आंटी' कहते हैं। मालविका जोशी ने इस रोल को बहुत शिद्दत से निभाया है। आंटी कन्या पूजन की हर छोटी-बड़ी तैयारी पूरी लगन से कर

रही हैं लेकिन सुबह होते ही सब उल्टा-पुल्टा हो जाता है। घर की मदद करने वाली मीना नहीं आती। प्लेटें, चढ़ावा, यहां तक कि पूजा की दरी भी गायब हो जाती है। घर वाले बेचैन और चिढ़े हुए हैं। आंटी की घबराहट बढ़ती जाती है। उनकी यह परेशानी एक गहरी सच्चाई दिखाती है। औरतों पर ही अक्सर संस्कृति और धर्म की रस्मों को पूरी तरह निभाने का बोझ पड़ता है। रस्म की पवित्रता खतरे में लगती है और घर का माहौल तनाव से भर जाता है। फिल्म इन घरेलू बातों को बहुत सच्चाई से दिखाती है—छोटी-छोटी चिढ़, पीढ़ियों का फर्क, और नीचे-नीचे छिपी भक्ति—बिना ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर। जो शुरू में घरेलू हंगामे जैसी हल्की-फुल्की कॉमेडी लगती है, वो धीरे-धीरे बहुत गहरी सोच वाली बात बन जाती है। अचानक आई वो रहस्यमयी दीदी जब तनाव चरम पर पहुंचता है, तभी एक युवती जिसे सिर्फ. 'दीदी' कहा जाता है, अचानक आ पहुंचती है—और ठीक नौ लड़कियों के साथ। उसका आना ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खुद भेजा हो। वो शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई है। वो गायब चीजें ढूँढ निकालती है, सबको बैठाती है, बच्चों से प्यार से बात करती है और आंटी को ढाढ़स बंधाती है। एक पल में सब बदल जाता है। घर जो तनाव से भरा था, अब गर्मजोशी और सुखद माहौल से भर जाता है। लड़कियां हंसती-खेलती हैं, गाती हैं और पूजा में खुशी-खुशी हिस्सा लेती हैं। दीदी की शांत कार्यक्षमता और संयम से रस्म सिर्फ. रस्म नहीं रह जाती, बल्कि सच्ची भक्ति और एकता का रूप ले लेती है। ये लड़की (सवलीन कौर) घर की मालकिन आंटी से बात करते हुए एक कड़वी सच्चाई कह देती है—हमने अपनी नदियों को बहुत गंदा कर दिया है। उसकी बात उत्सव की खुशी में चुभ जाती है। खासकर दिल्ली में, जहां कंजक के बाद लोग यमुना किनारे जाकर बचे-खुचे प्रसाद को बहा देते हैं—और यही नदी को और गंदा करते हैं। यह पल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बिना ज़िम्मेदारी वाली रस्म सच में भगवान की इज्जत करती है? एक आध्यात्मिक मोड़ पूजा खत्म होने पर माहौल गंभीर हो जाता है। कबीर का भजन धीरे-धीरे बजता हैः 'मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।' यह भजन फिल्म के मुख्य संदेश को रेखांकित करता है। बिना ज्यादा खुलासा किए, कहानी में दीदी की असलियत का एक दमदार ट्विस्ट आता है। यह ट्विस्ट कहानी को घरेलू सच्चाई से आध्यात्मिक प्रतीक तक ले जाता है। यह बताता है कि भगवान सिर्फ. बड़ी-बड़ी रस्मों या दूर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि

इंसानी रिश्तों, दया और सच्ची श्रद्धा में बसता है। 'बिना नाम वाली लड़की' एक प्रतीक बन जाती है—उस पवित्रता की, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्लाइमेक्स ड्रामेटिक नहीं, बल्कि सोचने वाला है। फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहती है। रस्म से परे भक्ति

सच्चिदानंद जोशी की कहानी सामाजिक टिप्पणी के लिए जानी जाती है और फिल्म ने उसे अच्छे से अपनाया है। यह समावेशिता, औरतों की संस्कृति बचाने की भूमिका, और जाति-वर्ग-धर्म की दीवारों को तोड़ने की बात करती है। यह सवाल उठाती है कि क्या सिर्फ. यांत्रिक रस्में करने से भक्ति बची रहती है, या असली भक्ति तो सहानुभूति और खुले दिल में है। राहुल यादव का निर्देशन हास्य, कोमलता और दर्शन के बीच संतुलन बनाए रखता है। गति तेज है, एक्टिंग स्वाभाविक है और कहानी बिना बनावटी के है। मालविका जोशी ने आंटी के घबराहट से आश्चर्य तक के सफर को खूबसूरती से निभाया है। बच्चे भी बहुत सहज और मासूम लगते हैं। 'कंजकः द गर्ल विदाउट अ नेम' सिर्फ. त्योहार वाली शॉर्ट फिल्म नहीं है। यह एक कोमल याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति कठोर रस्मों में नहीं, बल्कि इंसानियत में है। आजकल जब त्योहार दिखावा बन जाते हैं, यह फिल्म हमें भक्ति का असली मतलब फिर से याद दिलाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम भगवान को कहाँ ढूँढते हैं। शायद वो दूर नहीं, हमारे बगल में ही है—बिना नाम का, अनदेखा, लेकिन बहुत असली। अपने शांत और सादे अंदाज में यह फिल्म भारतीय परंपरा, सामाजिक सोच और सार्थक कहानी का बेहतरीन मिश्रण है। जो भारतीय संस्कृति, सामाजिक मुद्दों और अच्छी कहानी पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म जरूर देखने लायक है—दिल को छूने वाली और लंबे समय तक याद रहने वाली।

(लेखक, जाने-माने पत्रकार और स्तंभकार हैं।)

पंजाब में व्यापारी बिना किसी डर के अपना व्यापार कर सकते हैं: चीमा

व्यापारियों की सुरक्षा और व्यापार करने में आसानी के प्रति भगवंत मान सरकार की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता

डी.जी.पी. गौरव यादव ने ट्रेडर्स कमीशन एवं कमेटियों के सदस्यों से पुलिस और व्यापारी वर्ग के बीच पुल के रूप में काम करने की अपील

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

व्यापारियों के विश्वास को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर तालमेल को संस्थागत बनाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, भगवंत मान सरकार ने पंजाब के व्यापारिक समुदाय के आसपास सुरक्षा घेरा सख्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन (पी.एस.टी.सी.), जिला और हलका स्तर की व्यापारिक कमेटियों तथा पुलिस प्रशासन के बीच संरचनात्मक और पूर्ण तालमेल के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि व्यापारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और यह राज्य के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने को आसान बनाना) का मुख्य हिस्सा है।

पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) गौरव यादव और आबकारी एवं कर आयुक्त जतिंदर जोरवाल के साथ पंजाब भवन से उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने व्यापारी वर्ग की सुरक्षा संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की सख्त हिदायतें जारी कीं। उन्होंने पुलिस प्रशासन और व्यापारी कमीशन तथा कमेटियों के सदस्यों को आपसी तालमेल मजबूत करने के निर्देश दिए, और जिला पुलिस प्रशासन को हिदायत की कि वे इस तहत की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्टें सीधे डी.जी.पी. कार्यालय के साथ लगातार साझा करें।

आबकारी एवं कर मंत्री ने कहा, 'सरकार का मकसद ट्रेडर्स कमीशन को अधिकृत करना और इसे राज्य भर के कारोबारियों तक पुलिस की पहुंच को महत्वपूर्ण ढंग से बेहतर बनाने के लिए एक मुख्य ताकत के रूप में इस्तेमाल करने का है।' इस संबंध में जमीनी स्तर पर निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने समूह जिला पुलिस बलों को व्यापारी कमीशन और कमेटी सदस्यों के साथ निरंतर बातचीत जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश दिया कि हलका और जिला स्तर पर व्यापारी कमीशन और कमेटी की सभी बैठकों में सक्षम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि पेश चुनौतियों को मौके पर ही हल किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा, 'ट्रेडर्स कमीशन एवं कमेटियों के सदस्यों या व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा साझा की गई किसी भी जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाना चाहिए।

संबंधित पुलिस अधिकारी सूचना देने वालों की सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेंगे, और इस ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही के परिणामस्वरूप सख्त जवाबदेही तय की जाएगी।' वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जिला और हलका स्तर की व्यापारी कमेटियों के पदाधिकारियों से भी अपील की कि वे कारोबारियों में विश्वास पैदा करें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि सरकार उनके घर-दहलीज तक सक्रिय पहुंच बनाने के लिए काम कर रही है ताकि वे बिना किसी डर या झिझक के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। इन्हीं विचारों को दोहराते हुए, डी.जी.पी. गौरव यादव ने ट्रेडर्स कमीशन और कमेटियों के सदस्यों से राज्य की पुलिस और व्यापारी वर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में काम करने की अपील की।

गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र के लिए पंजाब सरकार ने 10.50 एकड़ भूमि का कब्जा लिया: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़/जालंधर (जगमार्ग न्यूज)। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने करतारपुर रोड पर स्थित गांव नौगज्जा और फरीदपुर में 10.50 एकड़ भूमि का कब्जा लेकर 'गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र' की स्थापना की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह कदम गुरु रविदास जी की विरासत के सम्मान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। कब्जा लेने की पूरी प्रक्रिया वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, विधायक बलकार सिंह, पंजाब कृषि विकास बैंक के चेयरमैन पवन टीनू, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल और डेरा सच्चखंड बल्लां के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी की गई। इस मौके पर बोलते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, यह बहुत खुशी की बात है कि पंजाब सरकार ने अत्याधुनिक गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र के निर्माण के लिए 10.50 एकड़ भूमि का कब्जा हासिल कर लिया है।

इस भूमि का उपयोग अब गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को समर्पित एक विश्व स्तरीय संस्था बनाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने आगे घोषणा की, पंजाब सरकार इस जगह से हाई-टेंशन बिजली की तारों को शिफ्ट करने के लिए 55 लाख रुपये का खर्च वहन करेगी ताकि निर्माण कार्य बिना किसी देरी के सुचारू रूप से चल सके। वित्त मंत्री ने बताया, भूमि की रजिस्ट्री पहले ही हो चुकी है और अब कब्जा मिलने से यह प्रोजेक्ट लागू होने के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया है। इस केंद्र का डिजाइन और लेआउट प्लान डेरा सच्चखंड बल्लां के प्रतिनिधियों की सलाह से विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे ताकि निर्माण कार्य तुरंत शुरू हो सके। भगवंत मान सरकार के संकल्प को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र दुनिया भर में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के प्रसार और उनके संदेश को फैलाने वाले विद्वानों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पंजाब सरकार गुरु जी की आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत को संरक्षित करने और प्रचार करने के लिए दृढ़ है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व संबंधी साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा, गुरु रविदास जी की विरासत का सम्मान देने और गुरु जी द्वारा दर्शाई गई सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

'सरकार परेशानी-रहित और अनुकूल व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध'

चंडीगढ़ (जगमार्ग न्यूज)। पंजाब के वित्त, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि भगवंत मान सरकार व्यापार की सुविधा और सख्त टैक्स अनुपालन (टैक्स नियमों की पालना) के बीच मजबूती से संतुलन बनाए रख रही है, जिसके चलते पंजाब कर विभाग ने जी.एस.टी. व्यवस्था से पहले के कर बकायों की वसूली के लिए एक बड़ी मुहिम के तहत 91.10 करोड़ रुपये की 136 संपत्तियां अटैच की हैं। उन्होंने कहा कि जहां सरकार ने व्यापारियों को पुराने बकाये चुकाने में मदद करने के लिए एक बहुत ही लाभदायक एकमुश्त निपटान योजना की अवधि बढ़ाई है, वहीं लगातार डिफॉल्टर रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, पंजाब सरकार परेशानी-रहित और अनुकूल व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कारण हमने एकमुश्त निपटान योजना की अवधि बढ़ाई है, जो व्यापारियों को जी.एस.टी. व्यवस्था से पहले के उनके बकायों का सुगम माहौल में निपटान करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। आबकारी और कर मंत्री ने आगे कहा, हालांकि, जानबूझकर की गई कर चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 91 करोड़ रुपये से अधिक की 136 संपत्तियों को अटैच करना एक स्पष्ट संदेश देता है कि कर विभाग बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। मैं सभी संबंधित व्यापारियों से जोरदार अपील करता हूं कि वे अपने बकाये का निपटान करें और अपनी संपत्तियों को आगामी नीलामी से बचाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना का तुरंत लाभ उठाएं।

वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने छत्तबीर चिड़ियाघर में बाघ के तीन मादा बच्चों का नाम गरिमा, गुंजन और गजल रखा

छत्तबीर चिड़ियाघर का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च किया गया

सटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

छत्तबीर चिड़ियाघर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने मादा बाघ गौरी से जन्मे तीन मादा बच्चों का नाम गरिमा, गुंजन और गजल रखा।

उल्लेखनीय है कि ये तीनों बच्चे पिछले साल 5 नवंबर को जन्मे थे और अब इन्हें 3 महीने की उम्र पूरी होने के बाद किसी बड़े स्थान में छोड़ा जाएगा। इन तीनों में से दो का रंग सफेद है और एक का रंग भूरा है। इससे चिड़ियाघर में बाघों की कुल संख्या 10 हो गई है।

वन्यजीवों की देखभाल और लोगों को उनकी भलाई एवं संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में, मंत्री ने छत्तबीर चिड़ियाघर का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी लॉन्च किया। सोशल मीडिया को वन्यजीवों और प्रकृति संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए मंत्री ने आशा व्यक्त की कि इससे वन्यजीव संरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रयासों की पहुंच में और भी वृद्धि होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कटारूचक ने बताया कि अप्रैल माह में चिड़ियाघर की गोल्डन जुबली (50 वर्ष) पूरी हो जाएगी और विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण अवसर को भव्य ढंग से मनाने पर विचार किया जा रहा है।

इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा मुख्य वन्यजीव वार्डन बसंता राज कुमार और छत्तबीर चिड़ियाघर के फील्ड डायरेक्टर नलिन यादव भी उपस्थित थे।

पंजाब सरकार ने किया कृषि-प्रसंस्करण यूनिटों का विस्तार

कृषि मंत्री ने फाजिल्का जिले में तीन उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं का किया उद्घाटन

सटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र को और मजबूत करने तथा फसली विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए फाजिल्का जिले में स्थापित तीन प्रसंस्करण यूनिटों में व्यापक विस्तार किया है।

पंजाब के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने फाजिल्का जिले के गांव आलमगढ़ में पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.ए.जी.आर.ई.एक्स.सी.ओ.) द्वारा स्थापित तीन महत्वपूर्ण विस्तारित यूनिटों का उद्घाटन किया। इन यूनिटों में मिर्च प्रसंस्करण यूनिट, सिट्रस प्रसंस्करण यूनिट और हाई-टेक प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन नर्सरी शामिल हैं।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि ये यूनिटें न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेंगी, बल्कि पंजाब को उच्च-मूल्य वाले प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भी स्थापित करेंगी।

इस क्षेत्र के मिर्च उत्पादकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए खुड्डियां ने बताया कि पी.ए.जी.आर.ई.एक्स.सी.ओ. द्वारा आलमगढ़ में अपने मौजूदा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र में एक नई अत्याधुनिक मिर्च प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 मीट्रिक टन प्रति घंटा की विस्तृत क्षमता के साथ, यह यूनिट कुल मिर्च प्रसंस्करण क्षमता को 1 मीट्रिक टन प्रति घंटा से बढ़ाकर 4 मीट्रिक टन प्रति घंटा कर देगी। मंत्री ने कहा कि इस यूनिट में लाल और हरी मिर्च दोनों को विशेष रूप से निर्यात के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड मिर्च पेस्ट में प्रसंस्कृत किया जाएगा। यह पहल ताजा उत्पादों के लिए एक समर्पित खरीद चैनल प्रदान करेगी, जिससे स्थानीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और मिर्चों को धूप में सुखाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि हर सीजन में लगभग 6,500 मीट्रिक टन मिर्चों की प्रसंस्करण करके, यह यूनिट बेहतर कीमत सुनिश्चित करेगी और कटाई के बाद के नुकसान में भारी कमी लाएगी। पंजाब के प्रसिद्ध किन्नू उत्पादन से अधिकतम लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पी.ए.जी.आर.ई.एक्स.सी.ओ. द्वारा अपनी सिट्रस प्रसंस्करण यूनिट में बड़ा तकनीकी अपग्रेड किया गया है। इस अपग्रेडेशन के तहत उन्नत मशीनरी शामिल की गई है, जिसमें एक डीएसिडिफिकेशन यूनिट, एक विशेष सिट्रस पील ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट और एक डीबिटरिंग यूनिट शामिल है।

खुड्डियां ने बताया कि इस अपग्रेडेशन से किन्नू के जूस में लिमोनिन जैसे प्राकृतिक मिश्रणों के कारण होने वाली देरी से कड़वाहट की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा, 'कड़वाहट को हटाकर और एसिडिटी को नियंत्रित करके, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पंजाब का सिट्रस वैश्विक फ्लेवर मानकों पर खरा उतरे।' उन्होंने आगे कहा कि पील ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट उस उपकरण को बदल देगी जो पहले अवशेषों को उच्च-मूल्य वाले उत्पाद डी-लिमोनिन से भरपूर आवश्यक तेल में प्रसंस्कृत कर रही थी, जिसकी फूड फ्लेवर, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल उद्योगों में भारी मांग है। इससे स्वाद और लाभ दोनों में वृद्धि होगी।

हाई-टेक नर्सरी से सब्जियों की खेती में क्रांति लाने के बारे में बात करते हुए, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पी.ए.जी.आर.ई.एक्स.सी.ओ. द्वारा आलमगढ़ में एक नई हाई-टेक प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन नर्सरी स्थापित की जा रही है। यह यूनिट कॉर्पोरेशन की वार्षिक बीज उत्पादन क्षमता को 16 लाख से बढ़ाकर 40 लाख पौधों (सीडलिंग्स) तक पहुंचा देगी।

एलएमएचपी फैलोज नशे विरुद्ध पंजाब की निर्णायक जंग में 'लाईटहाऊस': डॉ.बलबीर सिंह

सेहत मंत्री ने एलएमएचपी फैलोज के पहले बैच के साथ किया विचार- चर्चा

सटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के सेहत मंत्री डा. बलबीर सिंह ने पंजाब भर में मानसिक सेहत और नशा छुड़ाओ मुहिम को ओर मजबूत करने के लिए एक अहम पहलकदमी के अंतर्गत लीडरशिप इन मैंटल हैल्थ प्रोगराम (एल.एम.एच.पी.) फैलोज के पहले बैंच के साथ मुलाकात की, जोकि राज्य में चल रही नशा विरोधी मुहिम ' युद्ध नशियां विरुद्ध' के द्वारा नशे को रोकने और मानसिक तंदरुस्ती बढ़ाने के लिए सरकार की वचनबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

यहां किसान भवन में हुई विचार चर्चा दौरान डा. बलबीर सिंह ने एल.एम.एच.पी. फैलोज को नशे विरुद्ध पंजाब की निर्णायक जंग में ' लाईटहाऊस ' बताया। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नशे के साथ जूझ रहा व्यक्ति '' समुद्र में तूफान की लपेट में आए जहाज जैसा होता है - अशांत और दिशाहीन।' ' उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह एक लाईटहाऊस जहाजों को सुरक्षित ढंग के साथ किनारे पर पहुंचा देता है, उसी तरह एल.एम.एच.पी. फैलोज भी नशा पीडितों और परिवारों को मुख्य धारा और स्थिरता की तरफ ले जाएंगे।

सेहत मंत्री ने जोर दे कर कहा कि फैलोज को सौंपी गई जिम्मेदारी अहम और परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा धैर्य और हमदर्दी की मांग करती है, लोगों को नशे की गिरफ़्त से बाहर निकालना किसी इनाम से कम नहीं। उन्होंने आगे कहा कि फैलोज को जनतक सेहत ढांचो में शामिल किया जा रहा है जिससे प्रणालियों को मजबूत किया जा सके, प्रक्रियाओं को मानक, निगरान विधियों में विस्तार और जिलों में संस्थागत सामर्थ्य बनाई जा सके।

मानसिक सेहत प्रोगराम में लीडरशिप को एक अग्रणी पहलकदमी बताते डा.बलबीर सिंह ने कहा कि यह भारत की पहली फैलोशिप है, जो विशेष तौर पर प्रणालीगत मानसिक सेहत मजबूती के द्वारा नशीले पदार्थों का दुरुपयोग रोकने पर समर्पित है। टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साईंसिज के सहयोग के साथ तैयार किया यह प्रोगराम, नशा छुड़ाओ केन्द्रों, ओओएटी केन्द्रों और जिला प्रशासनों को निगरानी करन, सामर्थ्य निर्माण और पूर्ण तालमेल में सहायता प्रदान करने के लिए जिले में प्रशिक्षण प्राप्त मानसिक सेहत पेशेवरों को तैनात करता है।

उन्होंने आगे बताया कि फैलोज की तरफ से युवाओं में नशे का प्रयोग को शुरू में ही रोकने के लिए स्कूलों, कालेजों और जनतक स्थानों के साथ भी सक्रियता के साथ संपर्क किया जाएगा। इस तरह रोकथाम, इलाज और पुर्नवास को एक व्यापक जनतक स्वास्थ्य ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा।

डा. बलबीर सिंह ने जोर देते कहा कि नशाखोरी सिर्फ पंजाब स्तर का मुद्दा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर की सेहत चुनौती है जिसका मुकाबला करने के लिए निरंतर और ढांचागत दखलअंदाजी की जरूरत है। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि एलएमएचपी माडल में देश भर के दूसरे राज्यो के लिए एक ठोस ढांचे के तौर पर उभरने की सामर्थ्य है।

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की दूरअन्देशी को उजागर करते उन्होंने कहा कि राज्य ने सेहत, शिक्षा और साफ पीने वाले पानी तक पहुंच को मानवीय विकास के मुख्य मापदण्डों के तौर पर प्राथिकता दी है। मानसिक सेहत सेवाओं को मजबूत करना और नशे के साथ निपटना, सभी के लिए बराबर और पहुंचयोग जनतक सेहत मुहैया करवाना, इस सोच के अंग है।

सेहत मंत्री ने फैलोज को शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि वह पेशेवर और नैतिक उत्तमता के मानक को कायम रखेंगे और पंजाब में नशाखोरी विरुद्ध चल रही लड़ाई में सुहिरदता के साथ योगदान देंगे।

युद्ध नशियां विरुद्ध: डीजीपी गौरव यादव ने जालंधर में अति-आधुनिक ए.एन.टी.एफ. रेंज दफ़्तर का किया उद्घाटन

तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ किया तैनात

सटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/ जालंधर

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य में चलाई जा रही मुहिम ' युद्ध नशियां विरुद्ध' को आगे बढ़ाते डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज जालंधर में पुलिस लाईनज में नई बनी अति- आधुनिक एंटी- नारकोटिकस टास्क फोर्स (एएनटीएफ) जालंधर रेंज इमारत का उद्घाटन किया। डीजीपी के साथ विशेष डीजीपी ए.एन.टी.एफ. कुलदीप सिंह, ए.डी.जी.पी. ए.एन.टी.एफ. नीलाभ किशोर और एडीजीपी स्टेट आर्म्ड पुलिस पंजाब एम.एफ.फारूकी भी मौजूद थे। जिक्रयोग्य है कि लगभग 9000 वर्ग फुट के कवरड क्षेत्र में फैली और 1.60 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनी यह अति-आधुनिक इमारत, रेंज की कार्य-कुशता को बढ़ाने और नशा तस्करी के साथ और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार की गई है। इसमें गजटिड अधिकारियों के लिए समर्पित दफ़्तर, जांच अधिकारियों और सहायक स्टाफ के लिए केबिन, रीडर का कमरा और एक आधुनिक कान्फ्रेंस रूम शामिल है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि अति- आधुनिक साधनों के साथ लैस इस सुविधा का उद्देश्य बड़े नशा तस्करों को रोक लगाना और राज्य में फैल रहे अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नैट्टवरकों को तबाह करना है। उन्होंने बताया कि इस विशेष यूनिट में मोबाइल और कंप्यूटर फोरेंसिक टूल, उन्नत डेटा विश्लेषण प्रणालियों, फोरेंसिक डेटा ऐक्सट्रैकशन, डीक्रिपशन और विश्लेषण सामर्थ्य के साथ-साथ क्रिप्टोकरंसी की ट्रेकिंग वाले उपकरण भी शामिल है। डीजीपी ने कहा, ड्रग इनफोरसमैंट में तकनीकी अपग्रेडेशन की विशेष जरूरत को पहचानते हमने न केवल बुनियादी ढांचा प्रदान किया है बल्कि इन उन्नत उपकरणों को चलाने में माहिर तकनीकी स्टाफ भी तैनात किया गया है।' ' उन्होंने बताया कि एएनटीएफ ने, अब 70, 000 से अधिक अपराधियों की आवाज वाले डेटाबेस और अन्य अति-आधुनिक विशेषताएं वाले पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम(पी.ए.आई.एस. 2.0) के साथ अपनी तकनीकी सामर्थ्य को और अपग्रेड किया है, जिससे अपराधियों को और अधिक आसानी के साथ काबू करने में मदद मिलेगी।

गैंगस्टरां ते वार का 30वां दिन: पंजाब पुलिस ने 645 ठिकानों पर छापेमारी कर 236 को गिरफ्तार किया

नशों के खिलाफ युद्ध के 355वें दिन 100 नशा तस्कर 7.7 किलोग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार

सटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम 'गैंगस्टरां ते वार' के 30वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिह्नित और मैप किए गए 645 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि 'गैंगस्टरां ते वार' - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग, जिसकी शुरूआत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने 20 जनवरी, 2026 को की थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।आज 30वें दिन पुलिस टीमों ने 236 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चार हथियार बरामद किए, जिसके साथ मुहिम की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10,214 हो गई है।

इसके अलावा 79 व्यक्तियों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई की गई है, जबकि 121 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 12 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि लोग गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर–93946-93946 के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपराध तथा अपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी भी साझा की जा सकती है।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम 'नशों के खिलाफ युद्ध' को 355वें दिन भी जारी रखते हुए, 100 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 7.7 किलो हेरोइन, 100 ग्राम अफीम, 6631 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 8760 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही केवल 355 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 50,338 हो गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने आज 37 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया है।

'तनाव-मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2,804 केंद्र एक-एक विद्यार्थी के लिए स्थापित किए गए'

बोर्ड परीक्षा देने वाले 6,695 विद्यार्थियों के लिए 3,255 विशेष केंद्र स्थापित: बैंस

11 अपंगता श्रेणियों को कवर करने वाला व्यापक नेटवर्क पंजाब सरकार के समावेशी दृष्टिकोण को दशार्ता है: डॉ. अमरपाल सिंह

सटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने वीरवार बताया कि भगवंत मान सरकार द्वारा 17 फरवरी, 2026 से शुरू हुई पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पंजाब भर में 6,695 विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए 3,255 विशेष परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, ताकि हर विद्यार्थी परीक्षा में सम्मान और विश्वास के साथ भाग ले सके।

उन्होंने बताया कि कुल 3,255 विशेष केंद्रों में से 2,804 केंद्र एक-एक विद्यार्थी के लिए स्थापित किए गए हैं, जो विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत, तनाव-मुक्त और अनुकूल परीक्षा वातावरण सुनिश्चित करते हैं।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा, हमारी सरकार समावेशी शिक्षा को मजबूत कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल परीक्षाएं करवाने तक सीमित नहीं है। यह हर बच्चे के लिए सम्मान और समानता सुनिश्चित करने के बारे में है। हम एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां हमारे विशेष क्षमता वाले विद्यार्थी खुद को सशक्त महसूस करें।

राइट्स टू पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप स्क्राइब और अतिरिक्त समय, रैंप और निर्बाध पहुंच वाली ग्राउंड-फ्लोर पर स्थित परीक्षा हॉल, ध्यान भटकाने को न्यूनतम करने के लिए अलग शांत कमरे, बड़े प्रिंट वाले प्रश्न पत्र और अन्य पहुंचयोग्य फॉमेर्टों के साथ-साथ जहां आवश्यक हो चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित की गई है।

इस पहल को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए, हरजोत सिंह बैंस ने कहा, यह एक न्यायपूर्ण और समान समाज निर्माण की दिशा में हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पंजाब सरकार हर विद्यार्थी को सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों से सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पीएसईबी के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने कहा कि सभी केंद्रों के सुपरिंटेंडेंट और स्टाफ को अपनी ड्यूटी पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से निभाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, 11 श्रेणियों की अपंगताओं को कवर करने वाले इन विशेष केंद्रों का नेटवर्क पंजाब सरकार की समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दशार्ता है और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा।

एआई शिखर सम्मेलन में 'नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं' की घोषणा

उद्देश्य : एआई को समावेशी, विकासोन्मुखी और वैश्विक रूप से प्रासंगिक बनाना है

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारत एआई शिखर सम्मेलन के दौरान गुरुवार को 'नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं' की घोषणा की गई जिनका उद्देश्य एआई को समावेशी, विकासोन्मुखी और वैश्विक रूप से प्रासंगिक बनाना है।

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026' के दौरान केन्द्रीय, रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के देशों और बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों के समक्ष आज इसकी घोषणा की।

इस प्रतिबद्धता को साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन, मेटा के चीफ एआई ऑफिसर एलेक्जेंडर वांग और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई सहित वैश्विक तकनीकी जगत के दिग्गजों के साथ शिरकत की।

फोटोः हि.स.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता का प्रमाण 'नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताएं' है। इसके तहत दो मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इनमें पहला, डेटा के माध्यम से रोजगार और आर्थिक बदलावों के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाना और दूसरा, एआई प्रणालियों को बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। यह पहल विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देश) के लिए एआई को समावेशी और प्रासंगिक बनाने की दिशा में भारत के नेतृत्व को दर्शाती है।

उल्लेखनीय है कि मंत्री ने सम्मेलन के तीसरे दिन (बुधवार) भारत के एआई गवर्नेंस विजन का अनावरण किया। इस दौरान सम्मेलन के कार्य समूहों के प्रमुख लक्ष्यों पर चर्चा हुई, जिसने वैश्विक एआई प्राथमिकताओं पर सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए मंच तैयार किया। उन्होंने जिम्मेदार नवाचार के लिए भारत का दृष्टिकोण वैश्विक एआई यात्रा के लिए मार्गदर्शक बताया। इस दौरान उन्होंने कहा था, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और इस शिखर सम्मेलन के व्यापक एजेंडे को निर्धारित करने में सात विषयगत कार्य समूहों के निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये परिणाम रोडमैप के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। साथ ही सहयोग नवाचार और एक उत्तरदायी एआई इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा भी तय करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने कहा, एआई के प्रति हमारा दृष्टिकोण 'सतर्कतापूर्ण उत्साह' का है। हम इसके जोखिमों और नियमों के प्रति सजग हैं। हम जोखिम प्रबंधन और वैश्विक मानकों को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि एक ऐसा समावेशी गवर्नेंस ढांचा तैयार हो सके जिसमें 'ग्लोबल साउथ' सहित सभी देशों की आवाज को सशक्त बनाया जा सके। सात विषयगत चक्र वैश्विक विशेषज्ञता और साझा दृष्टिकोणों को क्रियात्मक ढांचों में बदलने के भारत के प्रयासों को दर्शाते हैं। इनमें मानव पूंजी सामाजिक सशक्तिकरण सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई नवाचार तथा दक्षता विज्ञान, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण शामिल हैं।

इन कार्य समूहों ने सरकार उद्योग शिक्षा जगत और नागरिक समाज के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर एआई के भविष्य का रोडमैप तैयार किया है। महीनों के परामर्श के बाद अब इन लक्ष्यों को कार्यान्वयन की ओर ले जाने की तैयारी है।

फ्रांस के राष्ट्रपति ने की भारत के तकनीकी समावेशन की प्रशंसा

कहा, एआई के युग में एकजुटता जरूरी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने विश्व में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से हो रहे विकास एवं नवाचार को जिम्मेदारी पूर्ण और मानव केन्द्रित रखने पर जोर दिया तथा कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में होने वाली रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में देशों की स्वतंत्रता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना होगा।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने गुरुवार को एआई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत के डिजिटल परावर्तन की प्रशंसा की तथा यूरोप एवं फ्रांस की भारत के साथ मिलकर एआई को वैश्विक भलाई के लिए उपयोग में लाने के विजन को सामने रखा। उन्होंने एआई और डिजिटल दुरुपयोग के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इस दिशा में विश्व के देशों को मिल कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाचेषण को जिम्मेदारी तथा तकनीक को मानवता से जोड़ने की जरूरत है। भारत और फ्रांस इसमें मिलकर काम करेंगे। अपने भाषण का अंत उन्होंने 'जय हो' के वाक्य से किया। भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि एआई दुनिया को बदल रहा है। ऐसे में हमें एकजुट होने की जरूरत है और ऐसा नहीं करने से हम पीछे रह जायेंगे। उन्होंने कहा कि एक समय कहा जाता था कि प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे लेकिन आज अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। मैक्रों ने कहा कि दुनिया के किसी देश और कंपनी को किसी देश को एक मार्केट और डेटा के तौर पर देखने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एआई उत्पादकता बढ़ाने और मजदूर बाजार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में एआई सबको उपलब्ध हो यह बेहद जरूरी है। एआई को भाषाई तौर पर विविध होना चाहिए ताकि सब इसका उपयोग कर सकें। भारत इंपैक्ट सम्मिट का यही उद्देश्य है कि हम इस दिशा में प्रयास करें।

फोटोः हि.स.

इमैनुएल मैक्रों ने अपने भाषण की शुरुआत में भारत के तकनीकी समावेशन के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि यह बदलाव एक सभ्यता की कहानी बताते है। भारत ने वे किया जो दुनिया के अन्य देश नहीं कर पाये। भारत ने अपनी 'डिजिटल आइडेंटिटी' बनाई और डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई और पेमेंट सिस्टम बनाया जिससे लाखों लेन-देने हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआई क्षेत्र रणनीतिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। फ्रांस और भारत यूरोप के साथ एआई की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं और मानते हैं कि मॉडल, बुनियादी ढांचा और संतुलन बेहद जरूरी है। मैक्रों ने कहा, ... ऐसे समय में जब तनाव बढ़ रहा है, हमारे सभी डिजिटल उपकरणों को इस समावेशी दृष्टिकोण की ओर निर्देशित करने की तात्कालिकता बढ़ गई है और वास्तव में, भारत में मजबूत होने के लिए, लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप पर भी मजबूत होने के लिए।

पीएम सुशीला कार्की की नसीहत- नेपाली युवाओं के आक्रोश का सम्मान किया जाना चाहिए

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि युवाओं के आक्रोश का सम्मान किया जाना चाहिए और सशक्त लोकतंत्र को उनकी असहमति दबाने के बजाय सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

फोटोः हि.स.

काठमांडू में 76वें लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक प्रासंगिकता इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर रसोई में सब्जियों की कीमत तक हर क्षेत्र में दिखाई देनी चाहिए। पिछले साल हुए युवाओं के प्रदर्शनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह आंदोलन भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और भेदभाव के अंत की मांग करने वाला एक दर्पण था। एक मजबूत लोकतंत्र असंतोष को दबाता नहीं है, बल्कि उसे सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री कार्की ने जोर देकर कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने युवाओं की ऊर्जा और नैतिक आक्रोश की अनदेखी करके शांत नहीं रह सकता।

प्रधानमंत्री कार्की ने 5 मार्च को निर्धारित संसदीय चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल एक नियमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश को एक नए राजनीतिक दौर में ले जाने वाला ऐतिहासिक मोड़ है।

पाकिस्तान के कराची में सिलेंडर विस्फोट से इमारत ढही, मलबे में दबकर 16 लोगों की मौत

कराची। पाकिस्तान के कराची के रिहाइशी इलाके में गुरुवार तड़के एक इमारत में सिलेंडर विस्फोट के कारण 16 लोगों की मौत हो गई। धमाके के कारण इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया जिसके मलबे में दबकर लोगों की मौत हुई। कई घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जियो न्यूज के मुताबिक कराची के सोल्जर बाजार के गुल राणा कॉलोनी इलाका स्थित एक इमारत में गुरुवार तड़के करीब सवा 4 बजे सिलेंडर विस्फोट हो गया। इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई।यह धमाका गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से हुआ। हादसे के बाद राहत कर्मियों ने मलबे से कई लोगों को निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हादसे में छह महिलाएं और 4 बच्चों समेत कुल 16 लोगों की जान गई है जबकि 14 लोग घायल हैं।

उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

मराठा साम्राज्य के संस्थापक एवं 'हिंदवी स्वराज्य' के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने उनके अदम्य साहस, दूरदर्शी नेतृत्व और जनकल्याणकारी शासन को नमन करते हुए उनके आदर्शों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने एक्स संदेश में शिवाजी महाराज का स्वराज्य के वास्तुकार, धर्म के रक्षक, निर्भीक योद्धा और जनकेंद्रित शासन के समर्थक के रूप में स्मरण किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का जीवन आज भी साहस, न्याय और निस्वार्थ नेतृत्व की प्रेरणा देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने अल्पायु में ही हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया और राष्ट्र के कण-कण में स्वधर्म, स्वराज और स्वभाषा के लिए जीने-मरने की जिजीविषा जागृत की। उन्होंने हर वर्ग को संगठित कर राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए सशक्त सेना का निर्माण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवाजी महाराज को पराक्रम और प्रजावत्सलता का दिव्य संगम बताते हुए कहा कि उनका जीवन स्वाभिमान की स्वर्णिम गाथा है, जो युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मराठी में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें 'जाणता राजा' कहकर नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम और कल्याणकारी शासन से स्वराज्य के विचार को मजबूत किया तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत की संस्कृति की रक्षा की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शिवाजी महाराज को अदम्य पराक्रम का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य और न्याय का आदर्श है।

फोटोः हि.स.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हें महापराक्रमी शूरवीर और कुशल प्रशासक बताते हुए देशवासियों को शिवजयंती की शुभकामनाएं दीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज को शौर्य, दूरदर्शिता और न्यायप्रिय नेतृत्व का अद्वितीय प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन आज भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य के प्रणेता और शौर्य के शिखर पुरुष के रूप में स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन पराक्रम, न्याय और सुशासन का अद्वितीय समन्वय है।

दो दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंची प्रियंका गांधी, मां कामाख्या का लिया आशीर्वाद

एजेंसी (हि.स.)
गुवाहाटी

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में दो दिवीसय दौरे पर पहुंचीं। उनका मकसद आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को तेज करना है।

बोरझार में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद, प्रियंका गांधी पूजा करने के लिए सीधे कामाख्या मंदिर के लिए रवाना हो गयीं। हवाई अड्डे पर असम प्रदेश कांग्रेस पार्टी (एपीसीसी) के अध्यक्ष एवं सांसद गौरव गोगोई समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंदिर जाने के बाद, वह स्क्रीनिंग से जुड़ी कई बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के लिए रवाना हुईं। प्रियंका गांधी असम में एक ऐसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया की निगरानी कर रही हैं जिसे पार्टी नेताओं ने 'अपूर्व और संरचित' बताया है। वरिष्ठ पार्टी कार्यकताओं ने कहा कि यह पहली बार है जब कांग्रेस राज्य में इतनी व्यापक और परामर्शात्मक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया कर रही है।

फोटोः हि.स.

असम कांग्रेस के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि प्रियंका आने वाले महीनों में कई बार राज्य के दौरे पर आएंगी ताकि प्रगति की समीक्षा कर सकें, जमीन से प्राप्त फीडबैक का आकलन कर सकें और राज्य इकाई और केंद्रीय नेतृत्व के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित कर सकें।

पार्टी की कोशिश है कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इस संकेत के साथ कि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची केंद्रीय नेतृत्व के साथ परामर्श के बाद फरवरी के अंत तक जारी की जा सकती है। राज्य नेताओं ने कहा कि चुनाव की दौड़ तेज होने के साथ संगठनात्मक तैयारियों और उम्मीदवारों की पहचान के मामले में कांग्रेस अन्य पार्टियों से आगे है।

तमिलनाडु के मछुआरों की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र

चेन्नई। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 22 मछुआरों की रिहाई के लिए कदम उठाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र में विदेश मंत्री से आग्रह किया गया है कि वे तत्काल कूटनीतिक कदम उठाकर मछुआरों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित कराएँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम मछली पकड़ने के जेट्टी से समुद्र में गए तमिलनाडु के 18 मछुआरों और उनकी तीन मछली पकड़ने वाली नौकाओं को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी दिन एक अन्य घटना में रामनाथपुरम जिले के मंडपम मछली पकड़ने के बंदरगाह से समुद्र में गए चार मछुआरों को भी श्रीलंकाई नौसेना ने हिरासत में लिया है। मछुआरा समुदाय का जीवन और आजीविका पूरी तरह समुद्र पर निर्भर है। ऐसे में श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी से उनके परिवारों में भारी चिंता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। वर्तमान स्थिति के अनुसार 104 मछुआरे और 258 नौकाएं श्रीलंका की हिरासत में हैं।

रामकृष्ण परमहंस को 'स्वामी, कहने पर ममता को आपत्ति

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

चुनाव सर पर हों तो हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। गुरूवार को स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आदरपूर्वक नमन किया। ठीक वैसे ही जैसे वर्षों से करते आ रहे हैं। पर इस वर्ष उनके नाम के साथ सम्मानपूर्वक स्वामी जोड़ने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ह्लसांस्कृतिक असंवेदनशीलताह्व है। ममता बनर्जी का कहना है कि युगावतार श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव की जन्मतिथि जैसे पावन अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा उनके नाम के साथ ह्लस्वामीह्व उपसर्ग जोड़ना अनुचित है।

फोटोः हि.स.

मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि श्रीरामकृष्ण परमहंस को व्यापक रूप से ह्लठाकुरह्व के रूप में पूजा और सम्मान दिया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईश्वर है। उनके महाप्रयाण के बाद उनके संन्यासी शिष्यों ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भारतीय परंपरा के अनुसार उन्हीं शिष्यों को ह्लस्वामीह्व कहा गया। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि रामकृष्ण परंपरा की पवित्र त्रयी–ठाकुरझमांझस्वामीजी–के रूप में जानी जाती है। इसमें ठाकुर हैं श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव, मां हैं मां शारदा और स्वामीजी हैं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कि ह्लस्वामीह्व उपसर्ग गुरु के लिए नहीं, बल्कि रामकृष्ण संप्रदाय के संन्यासी शिष्यों के लिए प्रयुक्त होता है।

उल्लेखनीय है कि रामकृष्ण परमहंसदेव की जन्म जयंती पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए ट्वीट किया था- स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जन्म-जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।

नाम, लोगो का दुरुपयोग करने वाले एनजीओ पर सख्ती, मानवाधिकार आयोग का राज्यों को नोटिस

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है जो आयोग के नाम, लोगो और पदनामों का दुरुपयोग करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सख्त कार्रवाई तथा दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने गुरुवार को बताया कि कई एनजीओ खुद को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जैसे नामों से पंजीकृत करवा रहे हैं, जो सुनने में आधिकारिक वैधानिक निकाय जैसा लगता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये संगठन अध्यक्ष जैसे पदनामों का उपयोग कर जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन भ्रामक नामों के कारण लोग इन्हें आयोग का हिस्सा या उससे मान्यता प्राप्त समझ लेते हैं। इससे न केवल जनता का विश्वास कम हो रहा है बल्कि धन के गबन और जनादेश के दुरुपयोग की भी आशंका है। आयोग के अनुसार हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां ₹राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद₹ नाम का एक एनजीओ दिल्ली में पंजीकृत पाया गया जबकि वह कर्नाटक में सक्रिय है। इसके प्रचार सामग्री में नीति आयोग और विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध होने के बड़े-बड़े दावे किए गए हैं। इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को इस एनजीओ के पंजीकरण और गतिविधियों की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

इन मामलों के मद्देनजर आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को नोटिस जारी करके निर्देश दिया है कि आयोग के नाम या लोगो का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की तत्काल पहचान की जाए।

ऐलान 'रिलायंस के साथ जियो एआई में 10 लाख करोड़ रुपये का करेगा निवेश'

दुनिया एआई को लेकर दोराहे पर खड़ी है: मुकेश अंबानी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

देश के दिग्गज उद्योगपति एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनका समूह कृत्रिम मेधा (एआई) में सात साल के भीतर 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। अंबानी ने कहा कि दुनिया एआई को लेकर दोराहे पर खड़ी है, जहां एक रास्ता दुर्लभ, महंगी एआईऔर नियंत्रित डेटा की ओर ले जाता है, जबकि दूसरा रास्ता सस्ती एवं सुलभ एआई सुनिश्चित करता है।

फोटोः हि.स.

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इंपैक्ट समिट' में अपने संबोधन में मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई का सर्वश्रेष्ठ रूप अभी आना बाकी है। उन्होंने कहा कि एआई में अपार समृद्धि का युग लाने की क्षमता है। ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भारत के टेक इतिहास में एक अहम पल है। एक ऐसा पल जब भारत एआई को अपने विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए ड्राइविंग फोर्स में से एक बनाने का वादा करता है और 2047 तक पूरी तरह से विकसित देश बनने का सपना है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो, रिलायंस के साथ मिलकर इस साल से अगले सात वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह कोई सट्टा निवेश नहीं है। यह मूल्य वृद्धि के लिए नहीं है। यह धैर्यपूर्ण, अनुशासित राष्ट्र निर्माण में लगाई जा रही पूंजी है। उन्होंने कहा कि एआई में सबसे बड़ी बाधा प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि 'कंप्यूटिंग' की उच्च लागत है। इसमें गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जियो ने भारत को इंटरनेट युग से जोड़ा और अब यह इसे बुद्धिमता के युग से जोड़ेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम हर नागरिक, हर क्षेत्र एवं सामाजिक विकास के हर पहलू तक बुद्धिमता (एआई) पहुंचाएंगे। जियो यह सब उसी विश्वसनीयता, व्यापकता और बेहद किफायती कीमत के साथ करेगा, जिससे उसने संपर्क क्षेत्र (मोबाइल डेटा) में क्रांति ला दी थी।

अंबानी ने कहा कि हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट के गाइड, फिलॉसफर और लीडर हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनकी शानदार टीम भारत की महत्वाकांक्षा के हिसाब से इस समिट को इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गनाइज करने के लिए पूरी तारीफ के हकदार हैं। अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एआई पावर्ड विकसित भारत का विजन भी विकसित वैश्विक दक्षिण के लिए एक खाका है। उन्होंने आगे कहा कि अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो मेरा मानना है कि एआई बहुत ज्यादा चीजों के युग की शुरूआत कर सकता है। गरीबी रहित दुनिया और हमारे खूबसूरत ग्रह पर सभी 8 अरब लोगों के लिए खुशहाली का भविष्य अब नजर में है, पहुंच में है।

संक्षिप्त-समाचार

लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1236 और निफ्टी 365 अंक टूटा

नई दिल्ली। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच व्यापक बिकवाली से बाजार के दोनों प्रमख सूचकांक में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,236 लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 365 अंक टूट गया। शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी में एक फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स तीन सत्रों से जारी तेजी पर विराम लगाते हुए 1236.11 अंक यानी 1.48 फीसदी लुढ़ककर 82,498.14 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी 365.00 अंक यानी 1.41 फीसदी टूटकर 25,454.35 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में शामिल इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अडाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, आईटीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही। इस बीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.02 फीसदी बढ़कर 71.07 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एशिया के अन्य प्रमुख शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी तीन फीसदी और जापान का निक्की एक फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि हांगकांग और चीन के बाजार पारंपरिक चंद्र नववर्ष पर अवकाश के चलते बंद रहे। बुधवार को कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 283.29 अंक यानी 0.34 फीसदी उछलकर 83,734.25 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 93.95 अंक यानी 0.37 फीसदी की बढ़कर 25,819.35 पर बंद हुआ था।

नारकोटिक्स ब्यूरो ने मध्यप्रदेश के महू जिले में 48 किलो से ज्यादा मेथ जब्त की

नई दिल्ली। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने मध्य प्रदेश में चलाए गए अब तक के सबसे बड़े अभियान में 43.820 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली मेथाम्फेटामाइन (एमडी) और 260 किग्रा से अधिक रसायन और अत्याधुनिक उपकरण जब्त किए हैं। इस पूरे अभियान में करीब 52 किलोग्राम एमडी जब्त करके तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील के थवलय गांव में एक कारखाने का भंडाफोड़ किया। सीबीएन ने तीन दिनों तक चले इस अभियान में 43.820 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली मेथम्फेटामाइन (एमडी), 260 किलोग्राम से अधिक रसायन और अत्याधुनिक उपकरण जब्त किए। इस पूरे अभियान में कुल 51.992 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन जब्त की गई। इस दौरान बरामद सभी प्रतिबंधित सामग्री और रसायनों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की नीमच शाखा को मिली एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीएन टीम ने 13 फरवरी की रात को मंदसौर में एक बस में यात्रा कर रहे दो यात्रियों से 8.172 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली क्रिस्टल एमडी बरामद की। इस अभियान के दौरान मंदसौर के बीपीएल चौराहा पर पकड़े गए दोनों व्यक्तियों पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए है, जिस घर में गुप्त प्रयोगशाला चल रही थी, उसके मालिक को भी कार्यवाही के दौरान हिरासत में लिया गया। कृत्रिम दवाओं के निर्माण और वितरण में शामिल व्यापक नेटवर्क की पहचान करने और उसे नष्ट करने के लिए आगे की जांच जारी है।

बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में ईडी ने अनिल अंबानी को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी को बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में नया समन जारी करके 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश होने के लिए तलब किया है, क्योंकि वे बुधवार को निर्धारित तारीख पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनकी पत्नी टीना अंबानी को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है, लेकिन उनके पेश होने के लिए नई तारीख से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत उनके अलग-अलग बयान दर्ज करने के लिए उन्हें 26 फरवरी को बुलाया है। अनिल अंबानी अगस्त, 2025 में एक बार ईडी के समक्ष पेश हुए थे। अनिल अंबानी की पत्नी और पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी भी ईडी के दूसरी बार समन जारी किए जाने के बावजूद 17 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने समक्ष नहीं हुई थीं। उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने के लिए 10 फरवरी को पहला समन जारी किया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं, जिसके बाद उन्हें नया नोटिस दिया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी ने उन्हें भी अगली तारीख दी है या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि टीना अंबानी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक लग्जरी आवासीय संपत्ति की खरीद से जुड़े धन के लेन-देन के संबंध में पूछताछ के लिए केंदीय जांच एजेंसी ने बुलाया है। ईडी ने हाल में इस मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहले जारी एक बयान में आरोप लगाया था कि आरकॉम की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान 2023 में न्यूयॉर्क स्थित इस संपत्ति को गर्ग ने धोखाधड़ी से बेचा था। ऐसा माना जा रहा है कि आरकॉम ने धोखाधड़ी से की गई इस बिक्री की जानकारी, 2025 में शेयर बाजार को दी थी।

हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 149 अंक उछला

नई दिल्ली। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बढ़त के साथ खुला। शुरूआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेज (बीएसई) का सेंसेक्स 147.46 अंक यानी 0.18 फीसदी उछलकर 83,881.17 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सेंचज एनएसई का निफ्टी 50.55 अंक यानी 0.20 फीसदी बढ़कर 25,869.90 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार में शुरूआती कारोबार के दौरान एआई समिट के प्रभाव से आईटी सेक्टर आज सबसे ज्यादा बढ़त बनाने वाला सेक्टर रहा, जिसमें 1 फीसदी की तेजी देखी गई है। इसके अलावा मेटल शेयरों में भी 0.60 फीसदी की मजबूती दिखी है। वहीं, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा दबाव दिखा और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.15 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा।

टी-20 विश्व कप: वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हराया, सुपर-8 में प्रवेश

वेस्टइंडीज ने इटली की टीम को 18 ओवर में 123 रन पर समेट दिया

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

आईसीसी टी-20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज ने अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में इटली को 42 रन से हराकर सुपर-8 में अजेय रहते हुए प्रवेश किया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 165/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया और जवाब में इटली की टीम को 18 ओवर में 123 रन पर समेट दिया।

तेज गेंदबाज शमार जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके, जबकि मैथ्यू फोर्डे ने तीन सफलताएं हासिल कीं।

होप की कप्तानी पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरूआत अच्छी नहीं रही। ओपनर ब्रेंडन किंग पारी की सातवीं गेंद पर आउट हो गए, जबकि शिमरॉन हेटमायर भी केवल एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पावरप्ले के अंत तक टीम का स्कोर 48/2 था।

इसके बाद कप्तान शाई होप ने जिम्मेदारी संभाली और रोस्टन चेज के साथ 64 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। चेज 24 रन बनाकर आउट हुए। होप ने मात्र 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 46 गेंदों में 75 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल रहे।

अंतिम ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड (24* रन, 15 गेंद) और मैथ्यू फोर्डे (16 रन, 8 गेंद) ने 14 गेंदों में 28 रन जोड़कर टीम को 165/6 तक पहुंचाया।

इटली की लड़खड़ाती पारी

166 रन के लक्ष्य का पीछा करने

फोटोः हि.स.

उतरी इटली की शुरूआत बेहद खराब रही। जस्टिन मोस्का 2 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि एंथनी मोस्का 19 रन (एक चौका, दो छक्के) बनाकर चलते बने। पावरप्ले के अंत तक टीम 37/3 के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी।

जेजे स्मट्स (24 रन) और बेन मनेन्ती (26 रन) ने कुछ देर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। ग्रांट स्टीवर्ट ने 12 रन बनाए, पर टीम बड़ा साझेदारी नहीं बना सकी।

जोसेफ-फोर्डे की घातक गेंदबाजी

शमार जोसेफ ने 4 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लेकर इटली की कमर तोड़ दी। मैथ्यू फोर्डे ने 3/25 के आंकड़े दर्ज किए, जबकि गुडाकेश मोती ने दो और अकील हुसैन ने एक विकेट लिया।

इटली की पूरी टीम 18 ओवर में 123 रन पर सिमट गई और वेस्टइंडीज ने 42 रन से जीत दर्ज कर सुपर-8 में दमदार एंट्री की।

संक्षिप्त स्कोर

वेस्टइंडीज 165/6 (20 ओवर) – शाई होप 75, रोस्टन चेज 24, शेरफेन रदरफोर्ड 24*; क्रिशन कालुगमाणे 2/24, बेन मनेन्ती 2/37।

इटली 123 ऑलआउट (18 ओवर) – बेन मनेन्ती 26, जेजे स्मट्स 24; शमार जोसेफ 4/30, मैथ्यू फोर्डे 3/25, गुडाकेश मोती 2/24।

वेस्टइंडीज 42 रन से विजयी।

हरमनप्रीत कौर बनीं महिला क्रिकेट की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी

एजेंसी (हि.स.)
कैनबरा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रचते हुए महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में मैदान पर उतरते ही उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

19 फरवरी को अपना 356वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए हरमनप्रीत ने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सुजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही वह महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास की सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गईं।

सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाली खिलाड़ियों की सूची में ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (349 मैच) तीसरे स्थान पर हैं। भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 333 मैच खेले हैं, जबकि इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स ने 309 मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा सोफी डिवाइन (305), हीथर नाइट (303) और डैनी व्याट-होज (302) भी इस सूची में शामिल हैं।

36 वर्षीय हरमनप्रीत कौर अब तक 6 टेस्ट, 161 वनडे और 189 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी हैं।

फोटोः हि.स.

टेस्ट में उन्होंने 200 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में उनके नाम 4,409 रन और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 3,784 रन दर्ज हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा हरमनप्रीत ने 35 महिला प्रीमियर लीग, 62 महिला बिग बैश लीग और 10 द हंड्रेड प्रतियोगिता के मुकाबले भी खेले हैं। उल्लेखनीय है कि उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने 2025 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराकर पहली बार विश्व खिताब जीता था।

दूसरे टी20 मुकाबले के टॉस के दौरान इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए हरमनप्रीत ने कहा, ह्यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है कि मैं टीम के लिए इसी तरह मेहनत करती रहूं और जितना संभव हो सके, खेलती रहूं।

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए सीपी प्लस को बनाया नया टाइटल स्पॉन्सर

एजेंसी (हि.स.)
मुंबई

पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी अब इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में नए जोश और महत्वाकांक्षा के साथ उतरने जा रही है। टीम ने वैश्विक सुरक्षा और निगरानी ब्रांड सीपी प्लस के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस समझौते के तहत सीपी प्लस आईपीएल 2026 के लिए पंजाब किंग्स का टाइटल स्पॉन्सर बनेगा, जिससे टीम की ब्रांड पहचान और व्यावसायिक दायरा और मजबूत होगा। विश्वास, सुरक्षा और तकनीक के बढ़ते महत्व के दौर में यह साझेदारी भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं को दर्शाती है। दोनों ब्रांड प्रदर्शन, विश्वसनीयता और नवाचार के मूल्यों से जुड़े हैं और देशभर के दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। सीपी प्लस वीडियो निगरानी, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, होम ऑटोमेशन और एंटरप्राइज सुरक्षा प्रणालियों सहित उन्नत समाधानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। नवाचार

फोटोः हि.स.

और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के चलते यह ब्रांड घरों, व्यवसायों और सार्वजनिक अवसंरचना में सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए जाना जाता है। इस साझेदारी के तहत पंजाब किंग्स और सीपी प्लस पूरे सत्र में डिजिटल अभियानों, मैदान पर विशेष गतिविधियों और प्रशंसक-केंद्रित पहलों की शुरूआत करेंगे। साथ ही स्टेडियम और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तकनीक आधारित इंटीग्रेशन के माध्यम से मैच अनुभव को और अधिक रोचक व इंटरैक्टिव बनाने की योजना है। सीपी प्लस के प्रबंध निदेशक आदित्य खेमका ने कहा कि क्रिकेट देश को जोड़ने वाला खेल है और पंजाब किंग्स के साथ यह साझेदारी उनके लिए विशेष महत्व रखती है।

भारतीय अंडर-20 महिला टीम स्वीडन में खेलेगी चार मैत्री मैच

नई दिल्ली। भारत की अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम स्वीडन में जारी तैयारी शिविर के दौरान वहां के क्लबों के खिलाफ चार मैत्री मैच खेलेगी। यह मुकाबले अप्रैल में थाईलैंड में होने वाले एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप 2026 की तैयारियों का हिस्सा हैं। भारतीय टीम, जिसे 'यंग टाइग्रेसेस' के नाम से भी जाना जाता है, 19 फरवरी को हैमरबी आईएफ की सीनियर टीम से भिड़ेगी। इसके बाद 22 फरवरी को टैबी एफके, 25 फरवरी को एंस्केडे आईके डैम और 28 फरवरी को कार्लबर्ग्स बीके के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय अंडर-20 महिला टीम 5 फरवरी को स्वीडन पहुंची थी और स्टॉकहोम के पास लिडिंगो स्थित बोसोन नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में प्रशिक्षण ले रही है। विदेशी परिस्थितियों में यह अभ्यास शिविर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहा है। एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप 2026 में भारत को ग्रुप 'सी' में रखा गया है। भारतीय टीम 2 अप्रैल को जापान, 5 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया और 8 अप्रैल को चीनी ताइपे के खिलाफ अपने ग्रुप मुकाबले खेलेगी। यह टूर्नामेंट थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा।

कतर ओपन : अल्कराज और सिनर सीधे सेटों में जीत दर्ज कर क्वार्टरफाइनल में पहुंचे

एजेंसी (हि.स.)
दोहा

कतर ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और इटली के यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे सेटों में जीत दर्ज कर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। विश्व नंबर एक अल्कराज ने फ्रांस के वेलेंटिन रोयर को 6-2, 7-5 से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने वर्ष 2025 में अपनी लगातार नौवीं जीत दर्ज की। दूसरे सेट में 2-5 से पीछे होने के बावजूद अल्कराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार पांच गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इससे पहले वह इस महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे।

अब 22 वर्षीय अल्कराज का सामना सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए रूस के सातवीं वरीयता प्राप्त करेन खाचानोव से होगा। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में अल्कराज का पलड़ा भारी रहा है। वहीं, विश्व नंबर दो

फोटोः हि.स.

यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन को 6-3, 7-5 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में हार के बाद उनका पहला टूर्नामेंट है। सिनर ने मैच में दमदार सर्विस का प्रदर्शन किया और पूरे मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी को ब्रेक प्वाइंट का मौका नहीं दिया। क्वार्टरफाइनल में सिनर का मुकाबला चेक गणराज्य के याकुब मेंसिक से होगा। शीर्ष-50 से बाहर के खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी जीत का सिलसिला अब 50 मैचों तक पहुंच गया है। अन्य मुकाबलों में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने पूर्व विश्व नंबर एक रूस के दानिल मेदवेदेव को 6-3, 6-4 से हराकर पिछले वर्ष बार्सिलोना ओपन के बाद पहली बार क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई।

विश्व कप से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ की 'कवर' भूमिका पर दी सफाई

मेलबर्न। टी-20 विश्व कप के ग्रुप चरण से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम चयन को लेकर सवालों के घेरे में है। इस बीच टीम के चयनकर्ता टोनी डोडेमेड ने स्टीव स्मिथ की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें केवल 'कवर' के रूप में टीम में शामिल किया गया था। 2009 के बाद यह पहला मौका है, जब ऑस्ट्रेलिया शुरूआती दौर से आगे नहीं बढ़ सकी। टीम को आईसीसी टी-20 रैंकिंग में 11वें स्थान पर मौजूद जिम्बाब्वे से चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी, जबकि श्रीलंका के खिलाफ भी वह पूरी तरह पिछड़ गई। इस निराशाजनक अभियान के बाद ऑस्ट्रेलिया में टीम चयन पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्टीव स्मिथ को शुरूआत में टीम में शामिल नहीं किया गया था, जिससे विवाद और बढ़ गया। बाद में उन्हें मिशेल मार्श के कवर के तौर पर बुलाया गया, जो ग्रोइन चोट के कारण शुरूआती दो मैच नहीं खेल पाए थे। इसके बाद जोश हेजलवुड के चोटिल होने पर स्मिथ को प्रतिस्थापन के रूप में जोड़ा गया। हालांकि, मार्श की वापसी के बाद स्मिथ को अंतिम एकादश में मौका नहीं मिला।

यूईएफए चैंपियंस लीग प्लेऑफः बोडो ग्लिम्ट ने इंटर मिलान 3-1 से हराया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के प्लेऑफ मुकाबलों में नॉर्वे के छोटे क्लब बोडो/ग्लिम्ट ने बड़ा उलटफेर करते हुए बुधवार को पिछले वर्ष के उपविजेता इंटर मिलान को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ बोडो/ग्लिम्ट ने अगले सप्ताह मिलान में होने वाले दूसरे चरण से पहले दो गोल की अहम बढ़त हासिल कर ली है।

घरेलू मैदान पर खेले गए मुकाबले में सोंड्रे फेट ने 20वें मिनट में कास्पर होग की बैकहील पास पर गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इंटर मिलान की ओर से फ्रांसेस्को पियो एस्पोसिटो ने हाफ टाइम से पहले बराबरी का गोल किया, लेकिन दूसरे हाफ में बोडो/ग्लिम्ट ने मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। 61वें मिनट में होग ने जेन्स पेटर हाउगे के लिए गोल का मौका तैयार किया और फिर तीन मिनट बाद स्वयं भी गोल दाग दिया। इंटर मिलान, जो पिछले तीन सत्रों

फोटोः हि.स.

में दो बार फाइनल में पहुंचा था, अब अगले दौर में जगह बनाने के लिए कठिन चुनौती का सामना करेगा। एक अन्य मुकाबले में न्यूकैसल ने अजरबैजान के कराबाग को 6-1 से करारी शिकस्त दी। एंथनी गॉर्डन ने पहले हाफ में चार गोल दागे और 33 मिनट के भीतर हैट्रिक पूरी की। बाकू के तोफिक बाखरामोव स्टेडियम में खेले गए इस मैच में न्यूकैसल हाफ टाइम तक 5-0 से आगे था। मैलिक थियाव और जैकब मर्फी ने भी गोल किए, जबकि कराबाग की ओर से एल्विन जाफरगुलियेव ने एकमात्र गोल दागा। दूसरे चरण से पहले न्यूकैसल अंतिम-16 में पहुंचने की मजबूत स्थिति में है। एटलेटिको मैड्रिड और क्लब ब्रूज के बीच मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा।

रश्मिका मंदाना से शादी की खबरों के बीच जगमगाया विजय देवरकोंडा का घर

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। भले ही दोनों कलाकारों ने अब तक अपनी शादी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। दरअसल, एक पैपराजी के शेयर किए गए वीडियो में विजय देवरकोंडा के हैदराबाद स्थित घर को रोशनी और फूलों से सजा हुआ देखा जा सकता है। घर की सजावट किसी उत्सव, खासकर शादी जैसे समारोह की ओर इशारा करती नजर आ रही है। वीडियो के सामने आते ही फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि दोनों सितारे जल्द ही अपने रिश्ते को नया नाम दे सकते हैं। वीडियो में घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसमें चारों ओर लाइटिंग और फूलों की सजावट दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर फैंस लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दोनों कलाकारों को बधाई संदेश भी भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में एक निजी समारोह में शादी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में केवल परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे। इससे पहले भी खबरें सामने आई थीं कि दोनों ने 3 अक्टूबर 2025 को एक निजी समारोह में सगाई की थी। हालांकि, इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रहे संकेतों ने फैंस की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह चर्चित जोड़ी जल्द ही अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगी।

'द केरल स्टोरी-2' का पैन-इंडिया प्लान

दो नई भाषाओं में ट्रेलर रिलीज

फिल्म निमार्ता विपुल अमृतलाल शाह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 झ गोज बियॉन्ड' अब बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है। मेकर्स ने फिल्म को हिंदी के साथ-साथ तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज करने का फैसला लिया है। इसी के साथ इन भाषाओं में फिल्म के ट्रेलर भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे फिल्म का दायरा और व्यापक हो गया है।

सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म अब क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए पैन-इंडिया दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाने जा रही है। फिल्म का उद्देश्य केवल हिंदी बेल्ट तक सीमित न रहकर साउथ भारतीय बाजारों में भी मजबूत पकड़ बनाना है।

फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कामाख्या नारायण सिंह ने किया है, जो अपनी संवेदनशील और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म 'भोर' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली थी, जबकि उनकी डॉक्यूमेंट्री 'जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड' को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

हाल ही में रिलीज हुए हिंदी ट्रेलर को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। उनके किरदारों के पोस्टर पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं, जो कहानी की गंभीरता और भावनात्मक गहराई को दर्शाते हैं।

मेकर्स का मानना है कि पहले भाग की सफलता और देशभर में उठी बहस को देखते हुए फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज करना जरूरी था, ताकि इसकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 'द केरल स्टोरी 2 झ गोज बियॉन्ड' 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि यह अपने पहले भाग की तरह एक बार फिर दर्शकों के बीच चर्चा और संवाद को जन्म देगी।

सूबेदार' का पहला गाना 'लल्ला' रिलीज, दमदार अंदाज में दिखे अनिल कपूर

अभिनेता अनिल कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'सूबेदार' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच फिल्म का पहला गाना 'लल्ला' रिलीज हो गया है, जिसमें अनिल का रौबदार और दमदार अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इससे पहले 11 फरवरी को फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसे भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'सूबेदार' का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है, जबकि अनिल कपूर

इसके सह-निमार्ता भी हैं। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। गाने 'लल्ला' को मशहूर गायक विशाल ददलानी ने अपनी दमदार आवाज दी है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। गाने का संगीत रोहन विनायक ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल ऋषि उपाध्याय ने लिखे हैं। टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गाने पर फैंस लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई विशाल ददलानी की आवाज की तारीफ कर रहा है तो कोई अनिल कपूर के अंदाज को कमबैक बता रहा है। फिल्म में अभिनेत्री राधिका मदान भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। 'सूबेदार' 5 मार्च को दर्शकों के बीच रिलीज के लिए तैयार है।

'रांझा' के साथ अमन नागपाल का म्यूजिक डेब्यू, दिग्गजों ने बढ़ाया हौसला

अमन नागपाल ने अपने पहले म्यूजिक वीडियो 'रांझा' के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में इस गाने के साथ-साथ उनकी म्यूजिक कंपनी 'स्काई एंटरटेनमेंट म्यूजिक' का भी आधिकारिक लॉन्च किया गया। यह शाम अमन के नए सफर की शुरूआत के साथ उनके बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल विजन का भी प्रतीक बनी। इस खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर

मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अमन नागपाल के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए उनके इस नए कदम की सराहना की। कार्यक्रम में राजा मुराद और अभिनेत्री निहारिका रायजादा भी शामिल हुईं, जबकि इवेंट की मेजबानी अभिनेत्री मनीनी डे ने की। म्यूजिक वीडियो 'रांझा' में अमन नागपाल के साथ ऋषभ बोर्चेटिया, सनाह मोइदुट्टी और के.के. शर्मा नजर आ रहे हैं। यह गीत प्यार, तड़प और बीते एहसासों की गहराई को दर्शाता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करता है। गुलशन ग्रोवर ने कहा कि अमन बेहद मेहनती और प्रतिभाशाली हैं और 'रांझा' एक दिल को छू लेने वाला गीत है, जिससे दर्शक जरूर जुड़ाव महसूस करेंगे।

आने वाले दिनों में मोहाली बनेगा नॉर्थ इंडिया का नंबर वन शहर : कुलवंत सिंह

विधायक ने कहा, शहर का बड़े स्तर पर सर्वांगीण विकास हो रहा

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में मोहाली नॉर्थ इंडिया का नंबर वन शहर बनकर उभरेगा, क्योंकि शहर का बड़े स्तर पर सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक समस्या के स्थायी समाधान के लिए इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित सड़कों की कनेक्टिविटी पूरी तरह सुनिश्चित की जा रही है। इन सड़कों के आपस में जुड़ने के बाद एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगा।

विधायक कुलवंत सिंह यह विचार पत्रकारों से बातचीत के दौरान व्यक्त कर रहे थे। वह मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन (एम.आई.ए.) की नव-निर्वाचित टीम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोहाली शहर में अब तक 10 चौक बन चुके हैं और आने वाले समय में 10 से 15 नए चौक और बनाए जाएंगे। इससे शहर अधिक खुला और व्यवस्थित दिखाई देगा तथा ट्रैफिक समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। विधायक ने कहा कि मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता के नेतृत्व में पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यह टीम उद्योगपतियों की आवश्यकताओं और समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाकर उनका शीघ्र समाधान करवाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही उद्योगपतियों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग से संबंधित प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं, जिससे आवेदन और स्वीकृतियां निर्धारित समय के भीतर मिल रही हैं। इस अवसर पर मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता के अलावा पूर्व प्रधान बलजीत सिंह, के. एस. माहल, बलवीर सिंह, हरिंदरपाल सिंह बिल्ला, गुरप्रताप सिंह, गुरचेत सिंह, गुरमुख सिंह भाटिया, महासचिव राकेश बिंज, प्रोफेसर सलूजा, जसपाल सिंह मटौर, रणदीप सिंह, तरलोचन सिंह मटौर, अकविंदर सिंह गोसल, सुखचैन सिंह, गुरमुख सिंह सोहल, हरमेश सिंह कुंबड़ा, बिक्रम सिंह तथा राजिंदर प्रसाद शर्मा भी उपस्थित थे।

पंचकूला नगर निगम ने कचरा फैलाने के विरुद्ध उठाया सख्त कदम

सफाई कर्मचारियों को नियम तोड़ने वालों की पहचान और चालान जारी करने के सख्त निर्देश

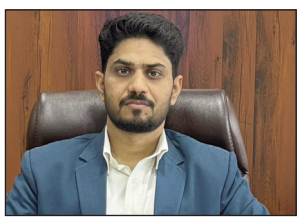

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

स्वच्छता और नागरिक अनुशासन बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए, आयुक्त श्री विनय कुमार के नेतृत्व में नगर निगम पंचकूला ने शहर में कूड़ा-कचरा फैलाने तथा अनधिकृत रूप से कचरा डंप करने के मामलों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करें और कचरा फैलाने या अवैध रूप से कचरा फेंकने में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों के विरुद्ध चालान जारी करें।

यह पहल पंचकूला के सभी सेक्टरों में निरंतर स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आयुक्त ने फील्ड अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने तथा नगर निगम अधिनियम एवं संबंधित स्वच्छता उपविधियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि निगम घर-घर कचरा संग्रहण सेवाओं और जन-जागरूकता अभियानों को सुदृढ़ कर रहा है, फिर भी यह देखा गया है कि अनधिकृत स्थानों पर लापरवाहीपूर्वक कचरा फेंकने की प्रवृत्ति सामूहिक प्रयासों को कमजोर करती है तथा जनस्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चालान जारी करने का उद्देश्य केवल जुरमाना लगाना नहीं, बल्कि इसे एक निवारक उपाय के रूप में अपनाते हुए जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को प्रोत्साहित करना भी है।

विनय कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन और नागरिकों दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों, दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे निर्धारित कचरा निपटान नियमों का पालन करें और सफाई टीमों के साथ पूर्ण सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि नगर निगम पंचकूला, एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक सतत शहरी वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जन-जागरूकता, सेवाओं तक आसान पहुँच और सख्त नियमों के संतुलित समन्वय के माध्यम से, निगम का उद्देश्य स्वच्छता मानकों को और मजबूत करना और शहर की क्षेत्रीय स्तर पर सबसे साफ शहरी केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा बनाए रखना है।

उन्होंने आगे बताया कि सभी फील्ड स्टाफ को सतर्कता बढ़ाने और सफाई नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर दिया जा रहा है जो अक्सर प्रभावित होते हैं, जैसे बाजार, खाली प्लॉट और सड़क किनारे के हिस्से, जहाँ अनधिकृत रूप से कचरा फेंकने की घटनाएँ सामने आई हैं।

अब 'रेडक्रॉस' बनेगा आधार सेवा का नया केंद्र

श्रम विभाग से मिली 35 एनरोलमेंट किट्स की मंजूरी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आमजन को मिलेगा सीधा लाभ

जिला स्तर पर रेडक्रॉस कार्यालयों में आधार मशीनें स्थापित होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट और अन्य संबंधित सेवाएं सहजता के साथ उपलब्ध हो सकेंगी। इससे आमजन को लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही, लघु सचिवालय, बैंक, डाकघर और अन्य स्थानों की बजाय उन्हें रेडक्रॉस में आधार कार्ड अपडेट की सुविधाए मुहैया करवाई जाएगी।

जिला कार्यालयों में शुरू होंगी आधार अपडेट की सेवाएं : अंकुश मिगलानी

हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने बताया कि जिला रेडक्रॉस कार्यालयों में अब आधार कार्ड भी अपडेट होंगे। हर जिले में केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड अपडेट करने के लिए तय की एजेंसी के सहयोग से आमजन को सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। रेडक्रास की ओर से श्रम विभाग से आधार कार्ड अपडेट करने के लिए 35 मशीनें ली हैं, जिन्हें जिला कार्यालयों में भेजा जाएगा। जिला कार्यालयों में आधार कार्ड अपडेट कार्य शुरू होने से आमजन को निकायों कार्यालयों में लगने वाली लंबी लाइनों से राहत मिलेगी।

हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी जिला कार्यालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करेगी। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से जिला रेडक्रॉस कार्यालयों में आधार मशीनें लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। रेडक्रॉस में आधार अपडेट की सुविधा शुरू होने से आमजन आसानी से नामांकन और अपडेट सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा। हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी ने जनसेवा और डिजिटलिकरण में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सोसायटी की ओर से श्रम कल्याण बोर्ड को प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों में आधार एनरोलमेंट किट्स मुहैया करवाने का प्रस्ताव भेजा गया था।

बोर्ड ने सोसायटी के प्रस्ताव पर मंजूर करते हुए 35 आधार एनरोलमेंट किट्स देने का फैसला लिया है। रेडक्रास में आधार एनरोलमेंट किट्स लगने से आधार अपडेट कार्य गति पकड़ेगा और त्रुटियों के बार-बार लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। हालांकि, इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत एजेंसी प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से चयनित रेडक्रॉस कार्यालयों में मशीनों की स्थापना की जाएगी।

भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा हेतु यूटी-स्तरीय सम्मेलन आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भारत की आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों तथा विभागों के बीच समन्वय की समीक्षा हेतु आज मुख्य सचिव श्री एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में यूटी-स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में गृह सचिव श्री मंदीप सिंह बरार, वित्त सचिव श्री दीपर्वा लखरा, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी, आयुक्त नगर निगम श्री अमित कुमार, निदेशक-सह-मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, यूटी चंडीगढ़ डॉ. नवजोत खोसा, उपायुक्त-सह-जिला जनगणना अधिकारी श्री निशांत कुमार यादव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्मेलन की शुरूआत जनगणना प्रक्रिया पर आधारित एक लघु फिल्म के प्रदर्शन से हुई, जिसके पश्चात निदेशक, जनगणना संचालन द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने कहा कि इस बैठक से जनगणना 2027 के संचालन को लेकर पूर्ण स्पष्टता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि विलंब के बावजूद जनगणना एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को इसमें सम्मिलित करना अनिवार्य है और प्रत्येक कार्मिक की भूमिका इसकी सटीकता एवं दक्षता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रशिक्षण एवं संचालन संबंधी दिशानिर्देशों को भली-भांति समझें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। प्रशिक्षण के उपरांत हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएशन (ल्छइउ) को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक परिवार का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 दो चरणों में संपन्न की जाएगी, जिसका प्रथम चरण हाउस-लिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना होगा। विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवधि फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है, जिसमें 19 फरवरी 2026 से 29 अप्रैल 2026 के बीच संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाउस-लिस्टिंग कार्य मई 2026 में तथा जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में की जाएगी।

संक्षिप्त-समाचार

तेजिंदर सिंह बने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग (फर्स्ट) सोसाइटी, सेक्टर 51-डी के अध्यक्ष

चंडीगढ़। इंडस्ट्रियलिस्ट्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग (फर्स्ट) सोसाइटी लिमिटेड, सेक्टर 51-डी, चंडीगढ़ के चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन्न हुए जिसमें तेजिंदर सिंह को अध्यक्ष चुना गया उनके अलावा परमजीत कौर को उपाध्यक्ष, प्रीतम सिंह गिल को महासचिव व के.आर. सिंगला को वित्त सचिव नियुक्त किया गया जबकि राजेश पाठक, रूप सिंह व योगेश मेहता कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

भाविप के दक्षिण जिला शाखा चुनाव सम्पन्न

चंडीगढ़। भारत विकास परिषद, चंडीगढ़ प्रांत के अंतर्गत दक्षिण जिला शाखा चुनाव 2026झ27 के चंडीगढ़ प्रांत के चुनाव निर्वाचन अधिकारी एवं उत्तर जिला संयोजक अजय सिंगला की देखरेख में संपन्न हुए। इसके तहत दक्षिण 1 के लिए एस. आर. शर्मा को अध्यक्ष, शक्ति चंद्र शर्मा को सचिव व शक्ति कुमार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया जबकि दक्षिण 2 के लिए रमेश शर्मा को अध्यक्ष, अनिल कुमार गर्ग को सचिव व अश्वनी नारंग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार दक्षिण 3 में हरजिंदर सिंह अध्यक्ष, जगदीपक कौर सचिव व एचसी गोयल कोषाध्यक्ष होंगे।

एससी अग्रवाल निर्विरोध बने सीएससीए के अध्यक्ष सभी पदाधिकारी भी बिना मुकाबला चुने गए

चंडीगढ़। चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन (सीएससीए) की नई गवर्निंग बॉडी के लिए आज संस्था के कार्यालय, करुणा सदन, सेक्टर 11 में चुनाव हुए, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारियों का चयन हुआ। एसोसिएशन के प्रधान के रूप में पूर्व प्रधान एससी अग्रवाल का चुनाव निर्विरोध हुआ। अन्य पदों में उप प्रधान के रूप में लवलीन कौर, प्रोजेक्ट सचिव पद पर लिली सूद, मेडिकल सचिव पद पर गोपाल कृष्ण सूद, वेलफेयर सचिव पद पर सुनीता महाजन, पब्लिक रिलेशन सचिव पद पर किरण कपूर, संगठन सचिव पद पर वीरेंद्र शर्मा, पब्लिकेशन सचिव पद पर राजेश आत्रेय और मेंबर रिलेशन सचिव के रूप में कमलेश अरोड़ा का चयन भी निर्विरोध हुआ। उक्त चुनाव दो वर्ष अर्थात 2026 से 2028 के लिए हुए हैं। ज्ञात हो कि सीएससीए को पूरे भारत वर्ष में सबसे बेहतर एसोसिएशन के रूप में वर्ष 2014 से 2025 तक चार बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसमें वर्ष 2014 एवं 2025 में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स चलाने तथा वर्ष 2016 एवं 2018 में सबसे बेहतरीन न्यूज लेटर बनाने का प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। इस एसोसिएशन में 3600 से अधिक सदस्य हैं तथा यह शहर के वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला सशक्तिकरण के लिए चंडीगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर निरंतर कार्यरत है। नई गवर्निंग बॉडी एक अप्रैल 2026 से अपना कार्यभार संभालेगी।

श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के कैडेट मानस रंजन ने गणतंत्र दिवस परेड में कॉलेज का नाम रोशन किया

चंडीगढ़। श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, सेक्टर 26 के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र एवं एनसीसी नौसैनिक विंग के कैडेट मानस रंजन ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में प्रतिष्ठित ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर (एआईजीओएच) टीम का हिस्सा बनकर कॉलेज का नाम गौरवान्वित किया। इस टीम ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कॉलेज की एनसीसी नौसैनिक विंग इकाई, जिसका नेतृत्व डॉ. सुरजीत सिंह कर रहे हैं, ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। विशेष उल्लेखनीय है कि कैडेट मानस रंजन चंडीगढ़ के कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौसैनिक विंग के एकमात्र कैडेट थे, जिन्हें इस विशिष्ट गार्ड ऑफ ऑनर टीम में शामिल किया गया। प्राचार्य डॉ. जसविंदर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन और उत्कृष्ट प्रदर्शन अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता का प्रतीक है, जिससे कॉलेज और एनसीसी इकाई को अत्यंत गौरव प्राप्त हुआ है।

जोश और जुनून के साथ संपन्न हुई एसडी कॉलेज की स्पोर्ट्स मीट, विजेता हुए पुरस्कृत

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज का दो दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट उत्साह के साथ संपन्न हो गया। इस स्पोर्ट्स मीट में छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कॉलेज द्वारा स्टूडेंट्स काउंसिल और एसडी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन चंडीगढ़ (एसडीपीटीएसी) के सहयोग से आयोजित इस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन यूजीसी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया गया। इस अवसर पर फिटनेस के महत्व को उजागर करते हुए फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज का संदेश भी दिया गया। आयोजन का उद्देश्य छात्रों को खेलों के प्रति प्रेरित करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। ओलंपियन बॉक्सर और कॉलेज की पूर्व छात्रा जैसमिन ने पहले दिन स्पोर्ट्स मीट का उदघाटन किया था। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपने पुराने संस्थान में लौटकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है।

वहीं, समापन समारोह के मुख्य अतिथि ज्वाइंट डायरेक्टर, स्पोर्ट्स, चंडीगढ़ डॉ. महेंद्र सिंह रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कॉलेज द्वारा शारीरिक शिक्षा को दिए जा रहे महत्व की सराहना की। डॉ. सिंह ने कहा कि खेल अनुशासित जीवन और व्यक्तित्व निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे आयोजन छात्रों में धैर्य, टीम भावना और जीवनभर स्वस्थ रहने की प्रेरणा विकसित करते हैं। समापन दिवस पर प्रमुख ट्रैक एंड फील्ड तथा टीम प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए। इनमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, 200 मीटर पुरुष दौड़, 200 मीटर महिला दौड़, 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले रेस, थ्री लैग्ड रेस (पुरुष), थ्री लैग्ड रेस (महिला), 4x200 मीटर रिले (पुरुष), 4x100 मीटर रिले (पुरुष), शॉट पुट, 100 मीटर पुरुष दौड़, 100 मीटर महिला दौड़ और रस्साकशी शामिल रहे। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के बीच जबरदस्त उत्साह, प्रतिस्पर्धा की भावना और उत्कृष्ट खेल भावना देखने को मिली।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स-46 में होगी अंडर-प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स एथलेटिक्स स्पोर्ट्स मीट

चंडीगढ़। मां तारा वेल्फेयर फाउंडेशन द्वारा अंडर-प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स (लड़के/लड़कियों) के लिए एथलेटिक्स स्पोर्ट्स मीट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -46, में तारीखः 22 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तकआयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की जानकारी देते अध्यक्ष आर बी रॉय और सचिव सुवेंदु मिश्रा ने बताया की सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एथलेटिक्स कोच द्वारा की जाएंगी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी मे 50 मीटर दौड़ (12 साल से कम उम्र का ग्रुप-लड़क, 100 मीटर दौड़ (15 साल से कम उम्र का ग्रुप-लड़के), 50 मीटर दौड़ (15 साल से कम उम्र का ग्रुप-लड़कियां), लॉन्ग जंप (15 साल से कम उम्र का ग्रुप-लड़के और लड़कियां), बैगरेस (12 साल से कम उम्र के लड़के), स्पून रेस (12 साल से कम उम्र की लड़कियां) के द्वारा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स प्रोग्राम होंगे।

चंडीगढ़ रोज फेस्टिवल 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय जागरूकता स्टॉल स्थापित किया

सिटी दर्पण संवाददाता

चंड़ीगढ़। भारतीय रिजर्व बैंक , चंडीगढ़ ने 20 से 22 फरवरी, 2026 तक आयोजित होने वाले रोज फेस्टिवल 2026 में जाकिर हुसैन रोज गार्डन में एक वित्तीय जागरूकता स्टॉल स्थापित किया है। यह पहल सक्रिय जागरूकता अभियानों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दोहराती है। इस स्टॉल में साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं, मनी म्यूल खातों के खिलाफ जागरूकता, बैंक खातों की री-केवाईसी, लावारिस डिपोजिट की जानकारी, करेंसी नोटों की सुरक्षा विशेषताएं और आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) से संबंधित विवरण सहित प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह स्टॉल आगंतुकों को अधिकारियों से सीधे जुड़ने और बैंकिंग और ग्राहक सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। आगंतुक ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, एलईडी स्क्रीन, डिजिटल स्टैंडी और पैम्फलेट जैसे इंटरैक्टिव टूल के माध्यम से दिन-प्रतिदिन के बैंकिंग मुद्दों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी का अनुभव कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के उच्च जुड़ाव और प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, साइबर धोखाधड़ी के खतरों और बैंकिंग लेनदेन करते समय सतर्क और सतर्क रहने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। आगंतुक इंटरैक्टिव क्विज में मौके पर ही भाग ले सकते हैं और आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं। रिजर्व बैंक इस बात पर जोर देता है कि एक मजबूत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय साक्षरता और जागरूकता महत्वपूर्ण है। रोज फेस्टिवल की व्यापक सार्वजनिक सहभागिता का उपयोग कर-के, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक बैंकिंग परिदृश्यों को सुरक्षित और आत्मविश्वास से नेविगेट करने के लिए ज्ञान प्रदान करना है।

दौरा | पीआईबी जयपुर की ओर से पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने चंड़ीगढ़ दौरे में रेल परियोजनाओं की जानकारी ली

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का कार्य प्रगति पर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंड़ीगढ़

पत्र सूचना कार्यालय और पीजीआईएमईआर चंड़ीगढ़ का किया दौरा

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), जयपुर द्वारा वरिष्ठ संपादकों एवं रिपोर्टरों का प्रतिनिधिमंडल 18 से 23 फरवरी 2026 के दौरान चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के दौरे पर है । इस दौरान रेलवे द्वारा संचालित अमृत भारत स्टेशन रेल परियोजनाओं का अवलोकन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए संयुक्त महाप्रबंधक सौरभ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 462 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर कार्य किया जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत आरएलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य परियोजना प्रबंधक बलबीर सिंह एवं संयुक्त महाप्रबंधक (परियोजनाएं) सौरभ सिंह ने किया। अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट की परियोजना की परिकल्पना एवं प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी तथा निर्माण स्थल का अवलोकन कराया। इस परियोजना का लक्ष्य स्टेशन को विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस करना और स्थानीय वास्तुकला को संरक्षित करना है। प्रतिनिधिमंडल ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत प्रो. विपिन कौशल, चिकित्सा अधीक्षक, पीजीआईएमईआर द्वारा किया गया। उन्होंने संस्थान की नैदानिक सेवाओं, रोगी देखभाल प्रणाली तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु किए जा रहे सुधारों की विस्तृत जानकारी दी। अस्पताल प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. नवीन पांडेय ने आयुष्मान भारतझ्रप्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभाव पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ ने लाभार्थियों का उपचार किया है, जिससे यह देश के अग्रणी सार्वजनिक तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल है। पीजीआईएमईआर जटिल एवं जीवनरक्षक उपचारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा ढांचे के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल को यह भी अवगत कराया गया कि कुछ मामलों में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दोषियों को दंड अथवा क्षतिपूर्ति की राशि इस फंड में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जरूरतमंद मरीजों को उन्नत उपचार उपलब्ध कराया जा सके। पत्रकारों को अंगदान एवं प्रत्यारोपण के क्षेत्र में संस्थान की उपलब्धियों, समन्वय तंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की भी जानकारी दी । पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने एंडोक्राइनोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. संजय भदादा से भी मुलाकात की, जिन्होंने मधुमेह एवं मेटाबोलिक बोन डिजीज की बढ़ती घटनाओं, विभाग में उपलब्ध विशेष सुविधाओं तथा भारी रोगी भार के बारे में जानकारी दी। दौरे में पत्रकारों ने देशभर के मरीजों को सुलभ, किफायती एवं उच्च गुणवत्ता वाली तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में पीजीआईएमईआर की कार्यकुशलता, व्यापकता एवं मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की। पत्रकार दल पत्रकार दल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रोपड़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ईलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोपड़ तथा डॉ बी आर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर का दौरा करेगा। पत्रकार दल का यह भ्रमण राज्य में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को समझने तथा मीडिया प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। दल ने पीआईबी का दौरा किया भी किया। इस अवसर पर निदेशक श्री प्रीतम सिंह ने दल से दौरे की विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर उपनिदेशक सपना, मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान व आशीष वर्मा मौजूद रहे।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण एवं वित्तीय स्थिति

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास आरएलडीए द्वारा ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन) मोड पर किया जा रहा है। यह परियोजना स्टेशन को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो चंडीगढ़ ट्राइसिटी क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगी। भौतिक प्रगतिः 87% कार्य पूर्ण, **वित्तीय प्रगतिः** 75%, कुल विकास क्षेत्रः 1,92,248 वर्गमीटर **परियोजना लागतः** 462 करोड़ रुपये, स्टेशन चंडीगढ़ एवं पंचकूला दोनों ओर जी+3 नए भवन (प्रत्येक 8,367 वर्गमीटर), **एयर कांकॉर्सः** 72 मीटर चौड़ा एवं 80 मीटर लंबा विशाल कांकॉर्स **बेहतर संपर्क व्यवस्थाः** 12 मीटर चौड़े दो नए फुट ओवर ब्रिज **दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएंः** 30 लिफ्ट एवं 10 एस्केलेटर

यात्री सुविधाएं एयरपोर्ट जैसा अनुभव प्रदान करने की दिशा में विकसित किया जा रहा है

वाणिज्यिक क्षेत्रः 4,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में फूड प्लाजा, रिटेल आउटलेट एवं रेस्टोरेंट, **विश्राम सुविधाः** 9 वातानुकूलित रिटायरिंग रूम एवं 3 डॉर्मिटरी (प्रत्येक में 8 बेड) **हरित ऊर्जाः** 1350 'हस्र क्षमता का सोलर प्लांट, स्मार्ट **प्रबंधनः** अत्याधुनिक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (इटर) एवं कमांड कंट्रोल रूम उपलब्ध होगा।

विशेषज्ञता के आधार पर लाभार्थियों का विवरण है

मेडिकल ऑन्कोलॉजीः 56,080
जनरल मेडिसिनः 42,870
कार्डियोलॉजीः 15,050
न्यूरोसर्जरीः 13,500
ऑर्थोपेडिक्सः 11,220
किडनी प्रत्यारोपणः 211

भागवत कथा सुनने से हमारे जीवन में नया संचार होता हैः कुलभूषण गोयल

पंचकूला। सेक्टर 20 स्थित शिव महाकाली मंदिर में श्री बांके बिहारी ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस पर भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर पंचकूला के पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गोयल ने कहा कि भागवत कथा सुनने से हमारे जीवन में नया संचार होता है। कार्यक्रम में सेक्टर 20 के पूर्व पार्षद सुशील गर्ग तथा ब्राह्मण सभा के पूर्व प्रधान एमपी शर्मा ने भी सहभागिता की और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राजाराम, सुरेंद्र गोयल, अजय गौतम और मोहित सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कथा व्यास पूज्य महाराज श्रीश्री 1008 महामंडलेश्वर विश्वामित्रानंद गिरी जी ने श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य प्राकट्य का मार्मिक वर्णन करते हुए कहा कि जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब भगवान स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करते हैं। उन्होंने बताया कि अत्याचारी राजा कंस के अत्याचारों से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी। तब भगवान ने मथुरा की कारागार में माता देवकी और पिता वसुदेव के यहाँ अर्धरात्रि में दिव्य रूप में अवतार लिया। उनके प्राकट्य से समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो उठा।